गुरुवार , 29 अक्टूबर 2026, ठाणे, मुंबई

दैनिक सिटी न्यूज मुंबई

सच का जोश

वर्ष - 15 • अंक - 64 CITY NEWS MUMBAI

महाराष्ट्र में Ola, Uber और Rapido पर सख्ती की तैयारी

चालकों के दस्तावेज और बैकग्राउंड की होगी जांच

माहिम में रैपिडो चालक पर ATS कार्रवाई के बाद महाराष्ट्र सरकार सख्त हुई है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने ऐप कैब चालकों के सख्त सत्यापन और नए कानून के निर्देश दिए। ओला, उबर और रैपिडो चालकों की सख्त जांच के निर्देश। दस्तावेजों में गड़बड़ी पर FIR दर्ज होगी। ऐप आधारित सेवाओं के लिए नए कानून की तैयारी। मुंबई में रैपिडो, ओला और उबर जैसी ऐप आधारित कैब और बाइक टैक्सी सेवाओं के चालकों के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। माहिम में एक रैपिडो चालक पर हुई एटीएस की कार्रवाई के बाद महाराष्ट्र सरकार ने ओला, उबर और रैपिडो जैसी ऐप आधारित कैब और बाइक टैक्सी सेवाओं के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। अधिकारियों के साथ बैठक परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने मोटर परिवहन विभाग के अधिकारियों को चालकों के दस्तावेजों और पृष्ठभूमि की सघन जांच करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। यात्रियों की



सुरक्षा को पुख्ता और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार एक नए कानून का मसौदा भी तैयार कर चुकी है, जिससे मनमानी करनेवाली इन कंपनियों पर कानूनी शिकंजा कसना तय माना जा रहा है। कैब चालकों के सत्यापन में ढिलाई बर्दाश्त नहीं माहिम में रैपिडो बाइक-टैक्सी चलाने वाले एक युवक के खिलाफ आतंकवाद निरोधक दस्ते द्वारा की गई कार्रवाई के बाद मंगलवार को यह अहम बैठक आयोजित की गई। संबंधित चालक पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने का आरोप लगा है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। हालांकि, प्राथमिक जांच में उसका पाकिस्तान के किसी व्यक्ति या संगठन से सीधे संबंध का कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए परिवहन मंत्री सरनाईक ने साफ किया कि यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर ऐप आधारित सेवा प्रदाताओं से जुड़े चालकों के सत्यापन और नियमों के पालन में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ऐप आधारित सेवाओं का दायरा जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसी अनुपात में कड़े नियमों का क्रियान्वयन भी अनिवार्य है। इस बीच सरनाईक ने स्पष्ट किया कि यात्रियों की सुरक्षा, मुंबई शहर में यातायात व्यवस्था में अनुशासन और कानून व्यवस्था बनाए ...शेष 7 पर

संजय राउत की बढ़ेंगी मुश्किलें! CJI पर टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत को CJI सूर्यकांत के खिलाफ दिए गए विवादित बयान के मामले में 17 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। CJI पर विवादित टिप्पणी मामले में संजय राउत की मुश्किलें बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने संजय राउत को 17 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने कहा। पत्रकार निखिल वागले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का निर्देश। शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता संजय राउत की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत के बारे में कथित तौर पर विवादित टिप्पणी करना उन्हें भारी पड़ गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संजय राउत को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। इस मामले



की अगली सुनवाई आगामी 17 नवंबर को होगी। एससीबीए ने दाखिल की है अवमानना याचिका संजय राउत की विवादित टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने कड़ी आपत्ति जताते हुए आपराधिक अवमानना याचिका दाखिल की है। एससीबीए ने संजय राउत के साथ-साथ पत्रकार निखिल वागले के खिलाफ भी याचिका दायर की है। हालांकि, कोर्ट ने पत्रकार निखिल वागले को 17 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से आने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का निर्देश दिया है। संजय राउत की ओर से नहीं मिला जवाब पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संजय राउत और निखिल वागले को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान वागले की तरफ से उनका माफीनामा और वकील पेश हुए, लेकिन संजय राउत की ओर से न तो कोई आधिकारिक जवाब दाखिल किया गया और न ही उनके वकील का वकालतनामा रिकॉर्ड पर आ सका। इसी कागजी कमी और अनुपस्थिति के कारण अदालत ने संजय राउत को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। क्या है संजय राउत का विवादित टिप्पणी मामला? यह विवाद संजय राउत द्वारा चुनाव आयोग के कामकाज और SIR के मुद्दे पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं से मिलने से सीजेआई सूर्यकांत के इनकार करने पर की गई तीखी आलोचना से जुड़ा है। राउत ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया था कि जज राजनीतिक हस्तियों के साथ लंदन में बैडमिंटन खेलते हैं और राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। संजय राउत के इस बयान के बाद अटॉर्नी जनरल ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया ...शेष 7 पर

सुनेत्रा पवार ने जीशान सिद्दीकी को बनाया मुंबई NCP का अध्यक्ष, बोले- वहिनी मां जैसी, पार्थ बड़े भाई



महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) ने जीशान सिद्दीकी को पार्टी का मुंबई अध्यक्ष नियुक्त किया है। सुनेत्रा पवार की NCP ने जीशान सिद्दीकी को मुंबई का अध्यक्ष बनाया। उमेश पाटिल को अपना राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया है। जीशान सिद्दीकी ने सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार का आभार जताया। उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने जीशान सिद्दीकी को पार्टी का मुंबई अध्यक्ष नियुक्त किया है। साथ ही एनसीपी ने उमेश पाटिल को अपना राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया है। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य (MLC) भी हैं। अपनी नियुक्ति के बाद जीशान ने महाराष्ट्र ...शेष 7 पर

महाराष्ट्र में सरकारी भवनों का बजट बढ़ाया तो अफसरों पर होगी कार्रवाई, PWD ने जारी किए सख्त निर्देश



सरकारी निर्माण कार्यों में बजट बढ़ोतरी पर महाराष्ट्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। बिना मंजूरी नक्शे या कार्यक्षेत्र बदलने पर संबंधित अफसरों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। सरकारी निर्माण का बजट बढ़ाने पर अफसरों की जवाबदेही तय। नक्शे या काम में बदलाव के लिए सचिव की मंजूरी जरूरी। बजट मंजूरी तक अधूरे काम की निविदा पर रोक। सरकारी निर्माण कार्यों में ने बढ़ते खर्च पर नकेल कसने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। सरकार ...शेष 7 पर

जरांगे पाटील की 500 करोड़ वाली ऑडियो क्लिप पर महायुति में घमासान, कैबिनेट बैठक में शिंदे गुट ने जताई नाराजगी

महाराष्ट्र कैबिनेट बैठक में मनोज जरांगे की वायरल ऑडियो क्लिप को लेकर महायुति में घमासान मच गया। शिंदे गुट के मंत्रियों ने भाजपा पर निशाना साधा और तीखी नाराजगी जताई। जरांगे पाटिल की 500 करोड़ वाली ऑडियो क्लिप पर शिंदे गुट के मंत्रियों में नाराजगी। कैबिनेट बैठक में भाजपा नेताओं से जुड़ी क्लिप का मुद्दा उठा। निधि वितरण में कटौती को लेकर भी शिवसेना मंत्रियों ने शिकायत की। मनोज जरांगे पाटील की ओर से वायरल की गई कथित ऑडियो क्लिप को लेकर महाराष्ट्र की महायुति सरकार में शामिल शिवसेना (शिंदे गुट) और भाजपा के बीच तनाव की चर्चा तेज हो गई है। मंगलवार



को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शिंदे गुट के मंत्रियों ने इस मुद्दे पर नाराजगी जताई। इसके साथ ही बैठक में सरकारी निधि के वितरण में कटौती का मामला भी उठाया गया। 500 करोड़ रुपये के कथित लेन-देन का आरोप वायरल ऑडियो क्लिप को लेकर दावा किया गया है कि मनोज जरांगे पाटील को कथित तौर पर मनाने या संभालने के लिए भाजपा की ओर से एकनाथ शिंदे को 500 करोड़ रुपये दिए गए थे। क्लिप में जरांगे द्वारा शिंदे से इस कथित रकम के बारे में सवाल पूछे जाने की बात सामने आई है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, एकनाथ शिंदे ने ऑडियो क्लिप से अपना संबंध होने और पैसे लेने के आरोपों से इनकार किया है। क्लिप में कथित तौर पर भाजपा से जुड़े लोगों की आवाज होने का दावा भी किया गया है। कैबिनेट बैठक में शिंदे गुट ने जताई नाराजगी सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार की बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के मंत्रियों ने यह मुद्दा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने उठाया। मंत्रियों ने वायरल क्लिप को लेकर अपनी ...शेष 7 पर

RJD ने ढहाया BJP का किला, पटना MLC चुनाव में उलटफेर पर झूमे तेजस्वी यादव, EC की पारदर्शिता पर उठाए सवाल

बिहार विधान परिषद चुनाव में जीत के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी के गढ़ में जीत पर खुशी जताई और चुनाव आयोग पर पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया। बिहार विधान परिषद चुनाव में जीत के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने खुशी जताई। बीजेपी के गढ़ में आरजेडी की जीत पर उन्होंने जनता को धन्यवाद दिया। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया। बिहार विधान परिषद चुनाव में चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। लगभग 30 साल बाद RJD ने बीजेपी का गढ़ ढहा दिया। बीजेपी पार्टी पर हुई इस जीत को लेकर तेजस्वी यादव गदगद हो उठे। पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के डॉ. संजीव कुमार ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नवल किशोर को 1,057 वोटों से हरा दिया। इस हार के साथ ही पटना शिक्षक सीट पर बीजेपी का लगभग 30 साल पुराना दबदबा खत्म हो गया है। तेजस्वी यादव ने जताई खुशी पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने विधान परिषद चुनावों में पार्टी के उम्मीदवारों की जीत पर खुशी जाहिर की। पटना में RJD नेता और बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, चाहे



विश्वविद्यालय हों या कॉलेज, शिक्षा ठीक से नहीं दी जा रही है। जो लोग जीते हैं, वे सदन में शिक्षकों और स्नातकों की समस्याओं को उठाएंगे। RJD नेताओं की प्रशंसा करते हुए तेजस्वी यादव ने RJD के सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं और उन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद दिया। साथ ही RJD के पक्ष में वोट डालने वाली जनता को धन्यवाद दिया। तेजस्वी यादव ने कहा, "यह खुशी की बात है कि हमने एक ऐसी सीट जीती है जो पहले BJP का गढ़ हुआ करती थी। इसके अलावा, मुझे चुनाव आयोग की भूमिका या यूं कहें कि पारदर्शिता की कमी पर भी बात करनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को घेरा RJD नेता ने कहा, "पूरी तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए थी। कई मौकों पर बेवजह देरी की गई। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में भले ही वोटों की संख्या कम होती है, लेकिन जिन चार सीटों में से तीन पर RJD जीती, उनके नतीजे शाम 6 बजे तक घोषित कर दिए गए थे। फिर भी, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से हमारे जीतने वाले उम्मीदवार को देर रात तक प्रमाण पत्र नहीं दिया गया।" BJP के इशारे पर काम कर रहा चुनाव आयोग मतगणना केंद्र पर सीसीटीवी को लेकर उन्होंने कहा, "वहां CCTV या निगरानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से BJP के इशारे पर काम कर रहा है। इसे देखते हुए, INDIA गठबंधन ने 1 नवंबर को चुनाव आयोग के खिलाफ एक मार्च और रैली आयोजित की है। हम इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और जनता के सामने अपना पक्ष रखेंगे।" बिहार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव परिणाम आपको जानकारी दें, कि तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी के नरेंद्र प्रसाद सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार भूषण कुमार झा को 594 वोटों से हराया।

जियो की धमाकेदार एंट्री से बदली कारोबारी समूहों की रैंकिंग, भावुक हुए मुकेश अंबानी

जियो प्लेटफॉर्म्स की शानदार लिस्टिंग के बाद रिलायंस समूह बाजार पूंजीकरण में टाटा समूह से आगे निकल गया। जियो का शेयर 21.4% प्रीमियम पर सूचीबद्ध हुआ। जियो प्लेटफॉर्म्स का शेयर 21.4% प्रीमियम पर सूचीबद्ध हुआ रिलायंस समूह का कुल मार्केट कैप बढ़कर 28.9 लाख करोड़ रुपये हुआ टाटा समूह 25.6 लाख करोड़ रुपये के साथ दूसरे स्थान पर रहा शेयर बाजार में जियो प्लेटफॉर्म्स की शानदार लिस्टिंग के बाद देश के सबसे मूल्यवान कारोबारी समूहों की रैंकिंग में बड़ा बदलाव आया है। बुधवार को जियो का शेयर 1,358 पर सूचीबद्ध हुआ, जिसके बाद रिलायंस समूह ने टाटा समूह को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल कर लिया। जियो की लिस्टिंग के बाद रिलायंस समूह की सूचीबद्ध कंपनियों का कुल मार्केट कैप बढ़कर 28.9 लाख करोड़ हो गया। वहीं, 25.6 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण के साथ टाटा समूह दूसरे और 16.6 लाख करोड़



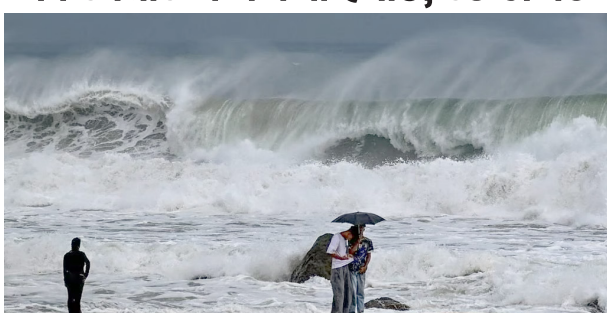
के साथ अदाणी समूह तीसरे स्थान पर रहा। इश्यू प्राइस से 21.4% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ जियो जियो प्लेटफॉर्म्स की शेयर बाजार में एंट्री से रिलायंस समूह की कुल बाजार वैल्यू में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। कंपनी का इश्यू प्राइस 1,119 था, जबकि शेयर 1,358 पर लिस्ट हुआ। इस तरह जियो के शेयर ने 21.4% के प्रीमियम के साथ बाजार में शुरुआत की। लि एक नई शुरुआतः आकाश अंबानी लिस्टिंग से पहले आकाश, ईशा और अनंत अंबानी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। जियो प्लेटफॉर्म्स के मैनेजिंग डायरेक्टर आकाश अंबानी ने कहा कि यह लिस्टिंग अंतिम पड़ाव नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। उन्होंने निवेशकों के साथ पारदर्शी संवाद बनाए रखने, वादों को पूरा करने और अपने काम के जरिए उनका भरोसा जीतने की प्रतिबद्धता जताई। स्टिंग के बाद जियो प्लेटफॉर्म्स का मार्केट कैप करीब 12.5 लाख करोड़ पहुंच गया। वहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो प्लेटफॉर्म्स की संयुक्त बाजार वैल्यू 28.7 लाख करोड़ हो गई। शेयरधारकों के लिहाज से भी जियो प्लेटफॉर्म्स की स्थिति खास रही। कंपनी के कुल शेयरधारकों की संख्या 79.8 लाख बताई गई है, जो देश में सबसे अधिक है। भावुक हुए मुकेश अंबानी मुंबई स्थित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में जियो प्लेटफॉर्म्स की लिस्टिंग के मौके पर पारंपरिक बेल-रिंगिंग समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, आकाश अंबानी, ईशा अंबानी और अनंत अंबानी शामिल हुए। रिलायंस बना देश का नंबर वन कारोबारी समूह जियो की लिस्टिंग का असर केवल कारोबारी समूहों की रैंकिंग तक सीमित नहीं रहा। बाजार पूंजीकरण के आधार पर रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध कंपनी बनी, जबकि जियो प्लेटफॉर्म्स ने दूसरा स्थान हासिल किया।

आंध्र प्रदेश में लैंडफॉल, 150 किमी/घंटे तक हवाएं; कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी



चक्रवात अर्नब का लैंडफॉल आंध्र प्रदेश के तट पर शुरू हो गया है। 150 किमी/घंटे तक हवाओं, भारी बारिश, बाढ़ और तूफानी लहरों का खतरा है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश में रेड अलर्ट जारी है। मछुआरों को समुद्र में होने वाली सभी गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाने की सलाह। समुद्री तटों पर लहरों की ऊंचाई 14 मीटर से अधिक हो सकती है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, 28 अक्टूबर को पूर्वी और मध्य भारत के मौसम पर अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान "अर्नब" का प्रभाव रहेगा। पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी से उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ते हुए, इस चक्रवात के 28 अक्टूबर की सुबह तक आंध्र प्रदेश और यनम के तटों से टकराने का अनुमान है। इस दौरान हवा की गति 125-135 किमी प्रति घंटा होगी, जो झोंकों के साथ 150 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। लैंडफॉल के बाद, तूफान धीरे-धीरे कमजोर होकर एक 'चक्रवाती तूफान' में बदल जाएगा। 28 अक्टूबर की शाम तक इसमें हवा की गति 90-100 किमी प्रति घंटा होगी, जो झोंकों के साथ 110 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।

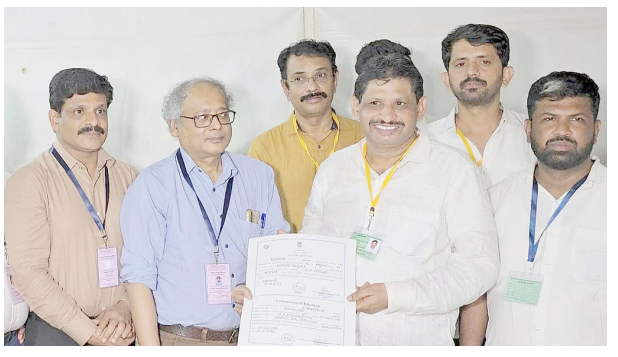
चक्रवात अर्नब की रफ्तार बढ़ने से तटीय इलाकों में दहशत, 150 KM/h की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, रेड अलर्ट



आंध्र प्रदेश में चक्रवात अर्नब का खतरा बढ़ गया है। IMD ने भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया। यानम-काकीनाडा क्षेत्र में लैंडफॉल की आशंका है। चक्रवात अर्नब के यानम-काकीनाडा क्षेत्र में लैंडफॉल की आशंका IMD ने भारी बारिश और 150 किमी प्रति घंटे तक तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया आंध्र प्रदेश और ओडिशा में हजारों आश्रय स्थल तैयार, बचाव टीमें तैनात आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में चक्रवात अर्नब का प्रभाव बढ़ने लगा है। जानकारी के मुताबिक, तूफान का लैंडफॉल शुरू होने की स्थिति बन रही है और यह प्रक्रिया काकीनाडा के पास यानम क्षेत्र के आसपास होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को चक्रवात की मौजूदा स्थिति से अवगत कराया है। मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं और तूफान की गति, दिशा तथा संभावित प्रभाव को लेकर हर घंटे अपडेट ले रहे हैं। उन्होंने जिला कलेक्टरों और संबंधित अधिकारियों के साथ कई समीक्षा बैठकें भी की हैं। प्रशासन की प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और संभावित नुकसान को कम करना है।

कर्नाटक में कांग्रेस का सूपड़ा साफ, BJP और JD-S गठबंधन ने जीतीं सभी 4 सीटें, 23 हजार वोटों के अंतर से मिली हार

कर्नाटक विधान परिषद चुनाव में BJP ने तीन सीटें बरकरार रखीं, जबकि JD(S) ने बेंगलुरु शिक्षक सीट जीती। कांग्रेस को चारों सीटों पर हार मिली। कर्नाटक विधान परिषद चुनाव में BJP ने तीन सीटों पर जीत हासिल की। JD(S) ने बेंगलुरु शिक्षक सीट पर जीत दर्ज की। कांग्रेस को चारों सीटों पर करारी हार का सामना करना पड़ा। देश के चार राज्यों कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में विधान परिषद चुनाव के परिणामों के लिए काउंटिंग जारी है। इनमें से कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर जीत दर्ज करते हुए कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया है। कर्नाटक में विधान परिषद की चार सीटों के लिए हुए चुनावों में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बेंगलुरु शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र कर्नाटक में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (BJP) और जनता दल (सेक्युलर) JD(S)



ने सभी चार सीटें जीत ली हैं। BJP ने अपनी तीन सीटें बरकरार रखीं, जबकि JD(S) ने कांग्रेस उम्मीदवार को हराकर बेंगलुरु शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र पर जीत हासिल की। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, BJP के समर्थन से चुनाव लड़ रहे JD(S) के ए. पी. रंगनाथ ने कांग्रेस के मौजूदा विधान परिषद सदस्य पुट्टन्ना को 908 वोटों से हराया। रंगनाथ को 10,810 वोट मिले, जबकि पुट्टन्ना को 9,902 वोट प्राप्त हुए। उत्तर-पूर्व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र उत्तर-पूर्व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में, BJP के मौजूदा सदस्य शशील जी. नमोशी ने कांग्रेस उम्मीदवार शरणप्पा मत्तूर को 3,297 वोटों से हराया। नमोशी को 15,596 वोट मिले, जबकि मत्तूर को 12,299 वोट मिले। इस निर्वाचन क्षेत्र से नमोशी की यह पांचवीं जीत है। दक्षिण-पूर्व स्नातक निर्वाचन क्षेत्र दक्षिण-पूर्व स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में, BJP के के. एम. सुरेश ने कांग्रेस उम्मीदवार शशि हुलिकुंटे मठ को बड़े अंतर से हराकर जीत दर्ज की। BJP उम्मीदवार ने कांग्रेस प्रत्याशी को 23,098 वोटों से हराया। पश्चिम स्नातक निर्वाचन क्षेत्र पश्चिम स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में, BJP के मौजूदा सदस्य एस. वी. संकानूर ने कांग्रेस उम्मीदवार मोहन लिंबिकाई को 9,323 वोटों से हराया। उन्हें 33,711 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को 24,388 वोट प्राप्त हुए। हालांकि इन चुनाव परिणामों से कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की स्थिरता पर कोई असर पड़ने की संभावना नहीं है, लेकिन इन्हें BJP और JD(S) के बीच बेहतर तालमेल के संकेत के रूप में देखा जा रहा है, जिससे विपक्षी गठबंधन को राजनीतिक लाभ मिल सकता है।

बिहार MLC चुनाव परिणाम: पटना शिक्षक सीट पर 30 साल बाद BJP हारी, RJD के संजीव कुमार जीते, स्नातक पर मतगणना जारी

बिहार विधान परिषद चुनाव में 4 शिक्षक सीटों के नतीजे घोषित। पटना शिक्षक सीट पर RJD के संजीव कुमार ने बीजेपी को हराया। स्नातक सीटों पर गिनती जारी। बिहार विधान परिषद चुनाव में 4 शिक्षक सीटों के नतीजे घोषित हुए। पटना शिक्षक सीट पर RJD के संजीव कुमार ने बीजेपी को हराया। बिहार की स्नातक सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। बि दरभंगा-पटना-तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र में परिणाम दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जन सुराज पार्टी के सुरेश प्रसाद राय ने चुनाव जीता। वहीं, चार स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोटों की गिनती बुधवार को भी जारी रही। पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जनता दल (यूनाइटेड) के नीरज कुमार ने जीत दर्ज की। अनंत सिंह समर्थित जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार अनुज सिंह तीसरे स्थान पर रहे। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में, सातवें दौर की गिनती के बाद निर्दलीय उम्मीदवार वंशीधर ब्रजवासी अपनी बढ़त बनाए हुए थे। हार विधान परिषद चुनाव में चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। बिहार में पटना की सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। 30 साल से कब्जा बनाए रही पार्टी को RJD ने हरा दिया है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया



कि पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के डॉ. संजीव कुमार ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नवल किशोर को 1,057 वोटों से हरा दिया। इस हार के साथ ही पटना शिक्षक सीट पर बीजेपी का लगभग 30 साल पुराना दबदबा खत्म हो गया है। तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी के नरेंद्र प्रसाद सिंह विजयी रहे। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी, निर्दलीय उम्मीदवार भूषण कुमार झा को 594 वोटों से हराया। सिंह को 2,945 वोट मिले, जबकि झा को 2,351 वोट प्राप्त हुए। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में, बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे राहुल राज ने जीत हासिल की। उन्होंने दूसरे वरीयता (सेकंड-प्रेफरेंस) के वोटों की गिनती के बाद अपने सबसे निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 1,815 वोटों से हराया।

स्नातक सीट पर मतगणना जारी दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में, दूसरे दौर की गिनती तक बीजेपी पार्टी से उम्मीदवार सर्वेश कुमार आगे चल रहे थे। उन्हें पहले दौर में 1,884 वोट मिले, जबकि RJD के अनिल कुमार झा को 1,647, कांग्रेस के रजनीकांत पाठक को 414 और जन सुराज पार्टी के मोहम्मद इम्तियाज को 935 वोट मिले। मतगणना के दूसरे दौर के बाद, सर्वेश कुमार को कुल 3,695 वोट मिले, जबकि अनिल कुमार झा को 3,220, रजनीकांत पाठक को 826 और मोहम्मद इम्तियाज को 1,819 वोट मिले। इस तरह, दूसरे दौर की गिनती के बाद भी भाजपा उम्मीदवार सर्वेश कुमार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं।

दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र नतीजों की घोषणा में देरी फिलहाल, दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के अंतिम नतीजों की घोषणा अभी नहीं हुई है।

बिहार MLC चुनाव में अनंत सिंह ने मानी हार, नीरज कुमार को बधाई देने से किया इनकार, पार्टी को लेकर दिया जवाब

बिहार ग्रेजुएट MLC चुनाव में हार पर अनंत सिंह ने कहा कि जनता ही असली मालिक है। JDU से निकाले जाने और पार्टी नेतृत्व पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। बिहार ग्रेजुएट MLC चुनाव में हार पर अनंत सिंह ने अपनी हार मान ली। JDU से निकाले जाने और पार्टी नेतृत्व पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। बिहार ग्रेजुएट MLC चुनाव में हार पर अनंत सिंह ने कहा कि जनता ही असली मालिक है। बिहार ग्रेजुएट एमएलसी चुनाव के नतीजों पर विधायक अनंत सिंह ने हार मान ली है। बिहार ग्रेजुएट एमएलसी चुनाव के नतीजों पर, जेडी(यू) से निकाले गए विधायक अनंत सिंह ने अनुज सिंह की हार पर बड़ा बयान दिया है। अनंत सिंह ने कहा, "अनुज सिंह हार गए हैं। अब तीसरे या चौथे स्थान की कोई बात ही नहीं है। वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। यह साफ है कि वह हार गए हैं।



अब क्या ही कहा जाए? जनता ही असली मालिक है, भगवान की तरह। जिसे वे चुनती हैं, वह जीत जाता है। जिसे नहीं चुनती, वह हार जाता है।" बिहार MLC चुनाव के नतीजों पर बोले अनंत सिंह बिहार एमएलसी चुनाव के नतीजों पर विधायक अनंत सिंह कहते हैं, "गिनती पूरी हो गई है और हम हार गए हैं। अब इसमें चर्चा करने वाली क्या बात है? क्या हमने किसी दुकान से वोट खरीदे थे? क्या हमने उन्हें तौलकर खरीदा था? जनता ही असली ताकत है, और भगवान उनके साथ हैं। जिन्हें जनता के वोट मिले, वे जीत गए। जिन्हें नहीं मिले, वे हार गए। वे जीत गए हैं और हम हार गए हैं। अब और क्या कहा जाए? मैं कभी भी पार्टी से नाराज नहीं रहा। मैं नीरज कुमार को बधाई क्यों दूं, और क्या ही कहा जा सकता है। देखते हैं, क्या उनका फोन आता है।" पार्टी से निष्कासन पर क्या बोले अनंत सिंह? हाल ही में पार्टी से निकाले जाने और पार्टी नेतृत्व के साथ अपने रुख पर उन्होंने बड़ा बयान दिया। अनंत सिंह ने JD(U) पार्टी से निष्कासन पर कहा, "पार्टी ही सर्वोपरि है। जो कुछ भी होता है, वह पार्टी का ही फैसला होता है। मैंने ऐसा कोई योगदान नहीं दिया है जिसके आधार पर मैं पार्टी पर अपना कोई दावा जता सकूं।" अनंत सिंह को JD(U) से क्यों निकाला गया? बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के चुनाव के दौरान, अनंत सिंह ने अपनी ही पार्टी JD(U) के उम्मीदवार नीरज कुमार का खुलकर विरोध किया था। इसके बजाय, उन्होंने 'जन सुराज' समर्थित उम्मीदवार अनुज सिंह का समर्थन किया और उनके लिए प्रचार भी किया। पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ चुनावी गतिविधियों में शामिल होने के कारण, JD(U) ने अनंत सिंह को छह साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है।

इस्लाम को दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती, मस्जिदों पर मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान



मौलाना अरशद मदनी ने मस्जिदों पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस्लाम को दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। उन्होंने मुसलमानों से सब्र और एकता बनाए रखने की अपील की। जमीयत उलेमा-ए-हिंद अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मस्जिदों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज जिन मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, वे एक दिन फिर आबाद होंगी। मदनी ने आरोप लगाया कि इस्लाम और धार्मिक संस्थानों को निशाना बनाया जा रहा है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मस्जिदों को लेकर एक बयान दिया है, जो अब काफी चर्चा में है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि आज जिन मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, वे एक दिन फिर आबाद होंगी और वहां दोबारा 'अल्लाहु अकबर' की सदाएं बुलंद होंगी। मदनी ने कहा कि जो आज सत्ता में हैं, वे कल नहीं रहेंगे, क्योंकि सरकारें आती-जाती रहती हैं। अरशद मदनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा कि इस्लाम को दुनिया की कोई ताकत न तो मिटा सकी है और न ही भविष्य में मिटा सकेगी।

पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान पर नड्डा का तीखा हमला, बोले दिवालिया हो चुकी कांग्रेस को खुद पर शर्म नहीं आती



बीते दिनों कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम को लेकर विवादित बयान दिया था। इसको लेकर बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। पीएम मोदी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर जेपी नड्डा का कांग्रेस पर हमला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम को लेकर दिया था विवादित बयान जेपी नड्डा ने कहा 2029 के चुनाव को कहा 2029 के लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजयी होंगे 25 अक्टूबर को पटना में डॉ. श्री कृष्ण सिंह की 139वीं जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे शामिल हुए थे। समारोह में पीएम मोदी को लेकर खड़गे ने अमर्यादित टिप्पणी कर दी थी। इसके बाद से ही बीजेपी के नेता खरगे पर हमलावर हैं।

लाल बिहारी यादव कौन हैं? जिन्होंने PM मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में BJP को हराया

वाराणसी खंड शिक्षक MLC चुनाव में लाल बिहारी यादव ने भाजपा को हराया। जीत के बाद अखिलेश यादव को श्रेय देते हुए उन्होंने पुरानी पेंशन और शिक्षकों के मानदेय जैसे मुद्दे उठाए। वाराणसी शिक्षक MLC चुनाव में लाल बिहारी यादव ने भाजपा उम्मीदवार प्रमोद मिश्रा को हराया। लाल बिहारी यादव ने जीत का श्रेय सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की नीतियों को दिया। पुरानी पेंशन बहाली, शिक्षकों के मानदेय और शिक्षा नीतियों को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन सीट पर समाजवादी पार्टी समर्थित उम्मीदवार लाल बिहारी यादव ने भाजपा प्रत्याशी प्रमोद मिश्रा को हराकर जीत दर्ज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मिली इस जीत को समाजवादी पार्टी के



लिए अहम राजनीतिक सफलता माना जा रहा है। जीत के बाद लाल बिहारी यादव ने इसे शिक्षकों के समर्थन और उनकी समस्याओं से जुड़े मुद्दों की जीत बताया। अखिलेश यादव की नीतियों को दिया श्रेय लाल बिहारी यादव ने जीत का श्रेय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने शिक्षकों की समस्याओं को लगातार उठाया है। पुरानी पेंशन बहाली, वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय, सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों की सेवा शर्तों तथा मदरसों के शिक्षकों के मानदेय जैसे मुद्दे प्रमुख रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि शिक्षकों ने इन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी के रुख पर भरोसा जताया है। उनके मुताबिक, चुनाव परिणाम भाजपा सरकार की शिक्षा नीतियों के प्रति शिक्षकों की नाराजगी को भी दर्शाता है। MLC Varanasi Election में पिछली बार से बढ़ा जीत का अंतर लाल बिहारी यादव ने बताया कि पिछली बार उनकी जीत का अंतर करीब 950 वोट था, जबकि इस बार यह अंतर 5 हजार से अधिक रहा। उन्होंने इसे शिक्षकों के बीच अपने समर्थन में बढ़ोतरी का संकेत बताया। हालांकि, जीत के अंतर और मतदान से जुड़े इन आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि चुनाव परिणामों के आधार पर की जानी चाहिए। शिक्षा और पुरानी पेंशन के मुद्दे उठाए जीत के बाद लाल बिहारी यादव ने भाजपा सरकार की शिक्षा नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि वित्तविहीन शिक्षकों और मदरसों के आधुनिक शिक्षकों को मिलने वाला मानदेय बंद होने से संबंधित वर्ग प्रभावित हुए हैं। उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली की मांग का भी जिक्र किया।

सम्पादकीय

घंटों परेशान रहे लाखों यात्री

घंटों बाधित रही रेल सेवा, यात्रियों की सुरक्षा और प्रशासन की जवाबदेही पर उठे गंभीर सवाल; संकट के समय जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता भी आई सामने मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की जीवनरेखा मानी जाने वाली उपनगरीय रेल सेवा में आई तकनीकी खराबी ने एक बार फिर महानगर की यातायात व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर कर दिया। सोमवार सुबह मध्य रेलवे के मार्ग पर हुई तकनीकी गड़बड़ियों के कारण रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। कई रेलगाड़ियां घंटों तक रास्ते में खड़ी रहीं, स्थानकों पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई और रोजाना कामकाज के लिए यात्रा करने वाले लाखों लोगों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इस घटना ने केवल रेल व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर ही नहीं, बल्कि संकट के समय प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। तकनीकी खराबी ने बिगाड़ा रेल यातायात का पूरा गणित मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लाखों नागरिक प्रतिदिन उपनगरीय रेल सेवा के सहारे अपने कार्यस्थलों, विद्यालयों, महाविद्यालयों और कारोबार तक पहुंचते हैं। महानगर में लंबी दूरी और सड़कों पर भारी यातायात के कारण रेल सेवा आम नागरिकों के लिए आवागमन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ऐसे में रेलगाड़ियों का कुछ समय के लिए भी बाधित होना हजारों परिवारों की दिनचर्या को प्रभावित कर देता है। सोमवार सुबह मध्य रेलवे के उपनगरीय मार्ग पर एक के बाद एक तकनीकी समस्याएं सामने आईं। कांजूरमार्ग स्थानक के पास संकेत व्यवस्था में खराबी और मुलुंड तथा ठाणे के बीच ऊपर लगे विद्युत तारों से जुड़ी समस्या के कारण रेलगाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हुई। इन घटनाओं के चलते रेल यातायात की गति धीमी पड़ गई और कई रेलगाड़ियों को लंबे समय तक रुकना पड़ा। सामान्य रूप से कुछ समय में ठीक हो सकने वाली स्थिति गंभीर अव्यवस्था में बदल गई और रेल सेवा को सामान्य होने में लगभग नौ से दस घंटे लग गए। घंटों रेलगाड़ियों में फंसे रहे यात्री रेल सेवा बाधित होने का सबसे अधिक असर उन यात्रियों पर पड़ा, जिन्हें समय पर कार्यालय, दुकान, विद्यालय या अन्य आवश्यक कामों पर पहुंचना था। रेलगाड़ियों के भीतर पहले से मौजूद भीड़ के बीच लंबे समय तक खड़े रहना यात्रियों के लिए बेहद कठिन हो गया। गर्मी, उमस, पीने के पानी की कमी और आगे की यात्रा को लेकर अनिश्चितता ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी। कई रेलगाड़ियां लंबे समय तक एक ही स्थान पर खड़ी रहीं। जब यात्रियों को यह स्पष्ट जानकारी नहीं मिली कि सेवा कब बहाल होगी, तो कुछ लोगों ने रेलगाड़ियों से उतरकर पटरियों के रास्ते निकटतम स्थानक तक पहुंचने का प्रयास किया। यह कदम बेहद जोखिम भरा था, क्योंकि रेल पटरियों पर दूसरी रेलगाड़ी के आने और बिजली के तारों से जुड़े खतरे बने रहते हैं। इस अव्यवस्था के बीच रेल पटरियां पार करने की कोशिश कर रहे कुछ यात्रियों की अलग-अलग घटनाओं में मृत्यु होने की खबरें भी सामने आईं। इन घटनाओं ने यह सवाल और गंभीर कर दिया कि जब रेल सेवा लंबे समय तक बाधित हो जाए, तो यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने और उन्हें निकटतम स्थानक तक पहुंचाने की व्यवस्था कितनी प्रभावी है। जानकारी के अभाव ने बढ़ाई यात्रियों की बेचैनी किसी भी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में तकनीकी खराबी होना असंभव नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति में यात्रियों को सही, समय पर और स्पष्ट जानकारी देना प्रशासन की बुनियादी जिम्मेदारी है। रेलगाड़ी कितनी देर रुकेगी, अगली रेलगाड़ी कब आएगी, वैकल्पिक मार्ग कौन-सा है और प्रभावित यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने की व्यवस्था क्या है—इन सवालों के जवाब समय पर मिलना जरूरी है। जब यात्रियों को स्थिति की सही जानकारी नहीं मिलती, तो अफवाहें फैलने लगती हैं और लोग अपनी समझ से रास्ता तलाशने लगते हैं। रेल पटरियों पर उतरना या जल्दबाजी में रेल मार्ग पार करना इसी असहाय स्थिति का खतरनाक परिणाम हो सकता है। इसलिए केवल उद्घोषणाएं करना पर्याप्त नहीं है। संबंधित अधिकारियों को नियमित अंतराल पर स्थिति की जानकारी देनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर कर्मचारियों की सहायता से यात्रियों को सुरक्षित दिशा में ले जाना चाहिए। रेल प्रशासन को ऐसी परिस्थितियों के लिए पहले से स्पष्ट कार्ययोजना तैयार रखनी चाहिए, ताकि तकनीकी खराबी आने पर यात्रियों को यह महसूस न हो कि उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। सड़क मार्ग पर भी यात्रियों को राहत नहीं मिली रेल सेवा ठप होने या धीमी पड़ने पर बड़ी संख्या में यात्री सड़क मार्ग की ओर मुड़ गए। इससे सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ गई और पहले से व्यस्त मार्गों पर यातायात का दबाव और अधिक हो गया। जिन यात्रियों को किसी भी हालत में समय पर पहुंचना था, उन्होंने बसों, टैक्सियों और अन्य साधनों का सहारा लिया। मांग अचानक बढ़ने पर यात्रियों को वाहन मिलने में कठिनाई हुई और कुछ स्थानों पर किराये को लेकर भी परेशानी की शिकायतें सामने आईं। इससे स्पष्ट हुआ कि मुंबई जैसे महानगर में रेल सेवा बाधित होने पर वैकल्पिक यातायात व्यवस्था यात्रियों का पूरा बोझ उठाने के लिए पर्याप्त नहीं है। महानगर की यातायात व्यवस्था को केवल रेलगाड़ियों के नियमित संचालन तक सीमित रखकर नहीं देखा जा सकता। रेल सेवा बाधित होने पर बसों की संख्या बढ़ाना, प्रमुख स्थानकों के बाहर यातायात का संचालन व्यवस्थित करना और यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों की जानकारी देना भी उतना ही आवश्यक है। संकट के समय जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर सवाल इस घटना ने जनप्रतिनिधियों की भूमिका को लेकर भी बहस तेज कर दी। शहर में महापौर, नगरसेवक, विधायक, सांसद और सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारी होने के बावजूद संकट के समय आम यात्रियों को तत्काल सहायता, पानी और स्पष्ट मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस हुई।

ब्राज़ील और सर्बिया में युवाओं की ताकत ने बदली राजनीति की दिशा

लूला दा सिल्वा की जीत और सर्बिया में छात्र आंदोलन की सफलता ने दिया बदलाव का संदेश; मतदान से लेकर जनआंदोलन तक युवाओं की सक्रियता बनी निर्णायक ताकत अंतरराष्ट्रीय विश्लेषण। दुनिया की राजनीति में युवाओं की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। लंबे समय से सत्ता में बैठे नेताओं, उनकी नीतियों और शासन के तरीकों को चुनौती देने में अब युवा केवल सड़कों पर उतरकर विरोध नहीं कर रहे, बल्कि मतदान और चुनावी भागीदारी के माध्यम से भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। ब्राज़ील में लूला दा सिल्वा की जीत और सर्बिया में छात्र आंदोलन से जुड़े उम्मीदवारों की सफलता इसी बदलते राजनीतिक माहौल की ओर संकेत करती है। दक्षिण अमेरिका के विशाल देश ब्राज़ील और यूरोप के छोटे देश सर्बिया के बीच भौगोलिक दूरी हजारों किलोमीटर की है। दोनों देशों की जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, सामाजिक परिस्थितियां और राजनीतिक इतिहास भी अलग-अलग हैं। इसके बावजूद इन दोनों देशों की राजनीतिक घटनाओं में एक समान सूत्र दिखाई देता है—युवाओं का बढ़ता असंतोष, सत्ता से जवाब मांगने की इच्छा और अपने भविष्य को लेकर निर्णय लेने की सक्रियता। इन घटनाओं ने यह सवाल भी खड़ा किया है कि क्या दुनिया के विभिन्न देशों में युवा मतदाता अब पारंपरिक राजनीतिक समीकरणों को चुनौती देने लगे हैं? क्या लंबे समय से प्रभावशाली रहे नेताओं के लिए केवल पुराने समर्थकों के भरोसे सत्ता बनाए रखना कठिन होता जा रहा है? ब्राज़ील और सर्बिया के घटनाक्रम इन प्रश्नों पर गंभीर चर्चा की आवश्यकता पैदा करते हैं। ब्राज़ील में लूला दा सिल्वा की जीत क्यों महत्वपूर्ण है? ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और उसकी राजनीति का प्रभाव पूरे क्षेत्र पर पड़ता है। यहां राष्ट्रपति पद के चुनाव में लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा के सामने फ्लावियो बोल्सोनारो की चुनौती थी। फ्लावियो पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के बेटे हैं और उन्हें कट्टर दक्षिणपंथी विचारधारा का समर्थक माना जाता है। चुनाव के पहले चरण में फ्लावियो बोल्सोनारो को बढ़त मिलने के बाद ऐसा माना जा रहा था कि दूसरे चरण में भी वे अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं। लेकिन अंतिम चरण में लूला दा सिल्वा ने जीत हासिल कर राजनीतिक अनुमानों को बदल दिया। इस परिणाम ने दिखाया कि शुरुआती बढ़त हमेशा अंतिम जीत की गारंटी नहीं होती और मतदाताओं का अंतिम निर्णय चुनाव की दिशा बदल सकता है। लूला की सफलता को केवल दो उम्मीदवारों के बीच मुकाबले के परिणाम के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। इसके पीछे मतदाताओं की प्राथमिकताएं, युवाओं की भागीदारी, सामाजिक मुद्दे और देश की भावी दिशा को लेकर लोगों की चिंताएं भी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। ब्राज़ील में नए मतदाताओं का पंजीकरण और युवाओं की चुनावी भागीदारी इस पूरे घटनाक्रम का अहम पक्ष रहा। युवा मतदाता रोजगार, शिक्षा, आर्थिक अवसर, सामाजिक समानता और अपने भविष्य से जुड़े सवालों को लेकर अधिक जागरूक हो रहे हैं। जब उन्हें लगता है कि किसी राजनीतिक नेतृत्व की नीतियां उनकी आकांक्षाओं से मेल नहीं खातीं, तो वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके बदलाव का रास्ता चुन सकते हैं। केवल लोकप्रियता नहीं, मतदाताओं का भरोसा भी जरूरी किसी भी लोकतंत्र में चुनाव जीतने के लिए केवल बड़े नेताओं का समर्थन, प्रचार और राजनीतिक पहचान पर्याप्त नहीं होते। मतदाता यह भी देखते हैं कि किसी उम्मीदवार की नीतियां उनके जीवन को किस प्रकार प्रभावित करेंगी। महंगाई, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक असमानता जैसे विषय चुनावी फैसलों पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। ब्राज़ील के चुनावी घटनाक्रम ने यह संदेश दिया कि किसी उम्मीदवार को शुरुआती दौर में बढ़त मिल जाने के बाद भी उसे अंतिम परिणाम आने तक मतदाताओं का भरोसा बनाए रखना पड़ता है। युवा मतदाता विशेष रूप से भविष्य की संभावनाओं को लेकर चिंतित रहते हैं। वे केवल पुराने राजनीतिक नारों के आधार पर निर्णय लेने के बजाय शासन की दिशा और अपने जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी विचार कर सकते हैं। हालांकि, किसी एक चुनाव के परिणाम से यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि सभी युवा एक ही विचारधारा का समर्थन करते हैं। युवाओं के बीच भी राजनीतिक मतभेद होते हैं। लेकिन जब बड़ी संख्या में युवा किसी मुद्दे पर सक्रिय होते हैं, तो वे चुनावी चर्चा और राजनीतिक प्राथमिकताओं को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। सर्बिया में छात्र आंदोलन ने कैसे बनाई अपनी जगह? सर्बिया में राजनीतिक असंतोष का एक अलग स्वरूप सामने आया। वहां राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच और उनकी राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ युवाओं का आंदोलन लंबे समय से चल रहा था। आर्थिक कठिनाइयों, अवसरों की कमी, शासन के तरीकों और लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली को लेकर असंतोष बढ़ता गया। इस आंदोलन ने केवल विरोध प्रदर्शन करने तक अपनी गतिविधियां सीमित नहीं रखीं। विद्यार्थियों और उनके समर्थकों ने चुनाव को बदलाव का रास्ता बनाने का प्रयास किया। उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों से ऐसे लोगों को आगे आने के लिए प्रेरित किया, जिन्हें वे सार्वजनिक जीवन में अधिक जिम्मेदार और भरोसेमंद विकल्प मानते थे। छात्रों ने उम्मीदवारों के चयन, प्रचार और नागरिकों तक अपनी बात पहुंचाने में भूमिका निभाई। इस प्रक्रिया में यह विचार महत्वपूर्ण रहा कि राजनीति केवल स्थापित दलों और अनुभवी नेताओं का क्षेत्र नहीं है। यदि आम नागरिक संगठित होकर भागीदारी करें, तो वे राजनीतिक व्यवस्था में नए विकल्प तैयार करने में योगदान दे सकते हैं। सर्बिया के घटनाक्रम का महत्वपूर्ण पक्ष यही है कि छात्र आंदोलन ने अपनी ऊर्जा को चुनावी भागीदारी से जोड़ने की कोशिश की। आंदोलन का उद्देश्य केवल सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करना नहीं था, बल्कि जनता के सामने एक वैकल्पिक राजनीतिक रास्ता प्रस्तुत करना भी था। लंबे समय तक सत्ता में रहने से पैदा हो सकता है असंतोष जब कोई नेता या राजनीतिक दल लंबे समय तक सत्ता में रहता है, तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती जनता का भरोसा बनाए रखना होती है।

शिक्षा, संस्कार और कर्तव्यबोध से ही होगा जिम्मेदार पीढ़ी और विकसित राष्ट्र का निर्माण

बच्चों में संस्कार केवल विद्यालय नहीं डाल सकता। बच्चे के व्यक्तित्व, विचारों और व्यवहार के निर्माण में परिवार की भूमिका सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण होती है। बच्चा अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में जो कुछ सीखता है, उसका बड़ा हिस्सा वह अपने माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार को देखकर सीखता है। माता-पिता जिस प्रकार दूसरों से बात करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, जरूरतमंदों की सहायता करते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, उसका सीधा प्रभाव बच्चे के मन पर पड़ता है। यदि घर में दूसरों के प्रति सम्मान, सहयोग, ईमानदारी और संवेदनशीलता का वातावरण है, तो बच्चा भी धीरे-धीरे इन्हीं गुणों को अपने जीवन का हिस्सा बनाने लगता है। इसके विपरीत, यदि घर में असहिष्णुता, भेदभाव, अनुशासनहीनता और केवल अपने अधिकारों की चर्चा होती है, तो उसका प्रभाव भी बच्चे के विचारों और व्यवहार पर दिखाई देने लगता है। इसलिए बच्चों को संस्कारित बनाने की जिम्मेदारी केवल विद्यालय या शिक्षकों पर डालकर परिवार अपनी भूमिका से अलग नहीं हो सकता। परिवार बच्चे की पहली पाठशाला है और माता-पिता उसके पहले शिक्षक। बच्चा पुस्तकों से जितना सीखता है, उससे कहीं अधिक वह अपने आसपास के लोगों के आचरण से सीखता है। यदि माता-पिता बच्चों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन स्वयं अपने व्यवहार में उसका पालन नहीं करते, तो बच्चे के लिए उस शिक्षा का वास्तविक अर्थ समझना कठिन हो जाता है। इसी प्रकार यदि बच्चों को अनुशासन का महत्व बताया जाता है, लेकिन घर के बड़े स्वयं नियमों का पालन नहीं करते, तो बच्चे के मन में अनुशासन के प्रति गंभीरता विकसित नहीं हो पाती। संस्कारों की वास्तविक शक्ति उपदेशों में नहीं, बल्कि उन आदर्शों में होती है जिन्हें बच्चा प्रतिदिन अपने जीवन में देखता है। परिवार के बाद विद्यालय की भूमिका शुरू होती है, जहां बच्चे को व्यक्तिगत व्यवहार से आगे बढ़कर सामाजिक जीवन की व्यापक समझ मिलती है। विद्यालय केवल पढ़ने-लिखने, गणित, विज्ञान और अन्य विषयों का ज्ञान प्राप्त करने का स्थान नहीं है, बल्कि यह वह परिसर भी है जहां विद्यार्थी सहयोग, समानता, सहिष्णुता, समयपालन, सामूहिक जिम्मेदारी और दूसरों के विचारों का सम्मान करना सीखता है। कक्षा में अलग-अलग परिवारों, आर्थिक परिस्थितियों और सामाजिक पृष्ठभूमियों से आने वाले विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं। इस वातावरण में बच्चे को यह समझने का अवसर मिलता है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, लेकिन सभी को समान सम्मान और अवसर मिलना चाहिए। विद्यालय में मिलने वाली शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी को केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने तक सीमित नहीं होना चाहिए। शिक्षा का वास्तविक अर्थ तब पूरा होता है, जब विद्यार्थी अपने ज्ञान का उपयोग स्वयं के विकास के साथ-साथ समाज के हित में भी करना सीखता है। जिस विद्यार्थी को पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझ में आता है, वह केवल पुस्तक में उत्तर लिखने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पानी बचाने, पेड़-पौधों की रक्षा करने और सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने के लिए भी प्रेरित होता है। इसी तरह नागरिक जिम्मेदारियों का ज्ञान रखने वाला विद्यार्थी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से बचता है, नियमों का सम्मान करता है और अपने आसपास होने वाली गलत गतिविधियों के प्रति जागरूक रहता है। शिक्षक की भूमिका इस प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षक केवल विषय का ज्ञान देने वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह बच्चों के विचारों को दिशा देने वाला मार्गदर्शक भी है। शिक्षक का व्यवहार, उसकी निष्पक्षता, विद्यार्थियों के प्रति उसका दृष्टिकोण और कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने का तरीका बच्चों के लिए सीखने का माध्यम बनता है। यदि शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के साथ समान व्यवहार करता है, उसकी बात ध्यान से सुनता है और गलती होने पर अपमानित करने के बजाय समझाने का प्रयास करता है, तो विद्यार्थी भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना सीखते हैं।

फिल्म रामायण में एआई के इस्तेमाल पर डायरेक्टर नितेश तिवारी ने तोड़ी चुप्पी, डबिंग को लेकर किया बड़ा खुलासा



डायरेक्टर नितेश तिवारी ने लॉस एंजिल्स में फिल्म रामायण के वर्ल्ड प्रीमियर के दौरान साफ किया है कि डबिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है। नितेश तिवारी ने फिल्म रामायण में एआई के इस्तेमाल को लेकर उठे सवालों पर सफाई दी। निर्देशक नितेश तिवारी के अनुसार डबिंग के लिए एआई का इस्तेमाल नहीं किया गया। फिल्म रामायण के ग्लोबल प्रीमियर के दौरान यह मुद्दा चर्चा में रहा। हाल ही में अमेरिका के लॉस एंजिल्स में फिल्म रामायण के भव्य ग्लोबल प्रीमियर का आयोजन किया गया, जहां फिल्म से जुड़ी कई जरूरी बातें सामने आईं। जब से फिल्म रामायण का निर्माण शुरू हुआ है, तब से इसे लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। खास तौर पर आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह की चर्चाएं तेज थीं। प्रीमियर के खास मौके पर खुद डायरेक्टर ने इन सभी अफवाहों पर विराम लगाते हुए एक साफ बयान दिया है, जिससे फिल्म से जुड़े कई भ्रम दूर हो गए हैं। एआई के इस्तेमाल पर नितेश तिवारी का बड़ा बयान फिल्म के इंटरनेशनल डेब्यू के दौरान जब एआई के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठे, तो डायरेक्टर नितेश तिवारी ने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि फिल्म की डबिंग प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग नहीं किया गया है। उनके अनुसार, फिल्म में जितने भी कलाकारों की आवाजें हैं, वे सभी असली और ओरिजिनल हैं जिन्हें कलाकारों ने खुद डब किया है। तकनीकी पक्ष पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि तकनीक के इस्तेमाल केवल लिप सिंक को सही करने के लिए किया गया है ताकि विदेशी दर्शक अपनी भाषा में फिल्म का सहजता से आनंद उठा सकें। इस सफाई के बाद उन सभी चर्चाओं पर विराम लग गया है जिनमें यह दावा किया जा रहा था कि कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर की मदद से कलाकारों की आवाजें तैयार की गई हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही फिल्म की उत्सुकता लॉस एंजिल्स में हुए इस शानदार वर्ल्ड प्रीमियर ने ग्लोबल मंच पर रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश की फिल्म रामायण की गूंज को और तेज कर दिया है। एकेडमी म्यूजियम ऑफ मोशन पिक्चर्स के थिएटर में आयोजित इस एक्सक्लूसिव स्क्रीनिंग में फिल्म रामायण के प्रति विदेशी दर्शकों और फिल्म समीक्षकों के रिएक्शन काफी पॉजिटिव रहे है।

नॉमिनेशन टास्क में झलका लव गिल का दर्द, कनिका और गूल्लू ने लगाया माही विज पर फेक होने का इल्जाम



स्काउट ओपी की गर्लफ्रेंड काशवी की एंट्री के बाद रिश्तों में तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। नॉमिनेशन टास्क के दौरान लव गिल भावुक हो गईं, वहीं स्काउट-मनीष की बहस की भी चर्चा में हैं। लव गिल का टूटा दिल, फूट-फूटकर रोईं स्काउट ओपी और मनीष गोयल में जोरदार बहस कनिका मान ने माही विज पर लगाए आरोप कलर्स टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस में वीकेंड के वार से अब तक इमोशंस का रोलर कोस्टर देखने के लिए मिल रहा है। स्काउट ओपी की गर्लफ्रेंड काशवी के वीकेंड का वार में लव गिल पर लगाएं गए इल्जामों के चलते वो पूरी तरह टूट गई है। बिग बॉस 20 के वीकेंड का वार एपिसोड में गेमर और यूट्यूबर स्काउट ओपी की गर्लफ्रेंड काशवी हीरानंदानी के दस्तक देने के बाद से घर का माहौल काफी बदला-बदला नजर आ रहा है। काशवी के द्वारा अपने बॉयफ्रेंड की क्लास लगाने जाने के बाद से स्काउट और लव गिल की दोस्ती में दरार नजर आने लगी है।

हाउसिंग सोसायटी के नियमों पर भड़की उर्फी जावेद, इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट कर उड़ाई धज्जियां



उर्फी जावेद ने आरोप लगाया है कि उनकी हाउसिंग सोसाइटी उन्हें अपने फ्लैट में कंटेंट शूट करने से रोक रही है। एक्ट्रेस ने नोटिस शेयर कर मेहमानों को रोकने पर भी सवाल उठाए हैं। उर्फी जावेद के घर में शूटिंग पर सोसायटी की रोक मेहमानों को रोकने और सामान चेक करने का आरोप उर्फी ने सोसायटी के नियमों पर उठाए सवाल अपने फैशन सेंस के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाली एक्ट्रेस उर्फी जावेद के लिए इन दिनों मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। हाल ही में उर्फी जावेद ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के माध्यम से सोसायटी में हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर खुलकर बात की है। सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर उर्फी जावेद ने इंस्टाग्राम स्टोरीज के माध्यम से ये बताया है कि उनकी हाउसिंग सोसायटी वालों ने उन पर नई पाबंदी लगा दी है। साथ ही उन्हें सोसायटी कंपाउंड के अंदर भी कंटेंच शूट करने से रोक लगा दी है। इससे पहले भी उर्फी अक्सर इन मुद्दों को लेकर सवाल उठा चुकी है। इंस्टाग्राम स्टोरी पर सोसाइटी वालों को लेकर उठाएं सवाल उर्फी जावेद ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर स्क्रीनशॉट शेयर कर लिखा कि मेरी सोसाइटी के हिसाब से, अपने ही फ्लैट के अंदर रील्स शूट करना गैर-कानूनी है। इसके अलावा अगली स्टोरी में उन्होंने लिखा कि उन्हें सिक्योरिटी स्टाफ के साथ बहस करते हुए देखा जा सकता है। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखाः "@नोयनदीपरक्षित (noy-andeeprakshit) इसके गवाह हैं कि इस आदमी ने मेरे घर आने वाले मेहमानों को गैर-कानूनी तरीके से रोक दिया। वे एक यूट्यूब शूट के लिए आए थे, लेकिन उनकी टीम को मेरे घर में घुसने से जबरदस्ती रोक दिया गया। मेरे स्टाफ का सामान भी गैर-कानूनी तरीके से चेक किया गया।" लोगों को बेनकाब करने की कही बात अगली स्टोरी में, उन्होंने बताया कि कैसे उनके मेहमानों को उनके अपार्टमेंट में घुसने से पहले अपना सामान दिखाने के लिए कहा गया। कैप्शन में लिखा था कि गैर-कानूनी!!!!! बहुत जल्द मैं इस आदमी का चेहरा सबके सामने लाऊंगी, और उन सभी लोगों को भी बेनकाब करूंगी जो मुझे इस हद तक परेशान कर रहे हैं। उर्फी जावेद द्वारा कल शेयर की गई स्टोरीज़ इस रियलिटी टीवी स्टार ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर दावा किया कि उन्हें परेशान करने का यह सिलसिला तब शुरू हुआ, जब उन्होंने सोसाइटी के एक नियम को लेकर पुलिस को बुला लिया था। यह नियम कहता था कि शाम 6 बजे के बाद अगर कोई मेहमान किसी निवासी के अपार्टमेंट में आता है, तो उसके लिए मकान मालिक से अनुमति लेनी होगी। एक स्टोरी शेयर करते हुए उर्फी ने लिखा कि मेरी सोसाइटी कमिटी ने मुझे परेशान करने के लिए एक नया नियम निकाला है - मैं अपने ही घर में कोई कंटेंट शूट नहीं कर सकती! उन्होंने आगे बताया कि कमिटी का तर्क है कि इस तरह की शूटिंग 'कमर्शियल' (व्यावसायिक) मानी जाएगी, क्योंकि यह कंटेंट सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है और इससे उनकी लोकप्रियता बढ़ती है। एक और स्टोरी में उन्होंने लिखा कि इससे उनके कमज़ोर पुरुष अहंकार (male ego) को ठेस पहुंची है। उन्होंने मेरे मकान मालिक से मुझे घर से बाहर निकालने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए अब 4-5 आदमियों को मुझे परेशान करने के लिए इतनी गिरी हुई हरकतें करनी पड़ रही हैं... मुझे खुद पर थोड़ा गर्व है। उर्फी ने यह भी आरोप लगाया कि अगर सोसाइटी के सदस्यों को शक होता था कि आने वाले लोगों के पास कैमरा या शूटिंग का कोई उपकरण है, तो वे उन्हें उनके घर में घुसने से रोक देते थे। उन्होंने दावा किया कि उनके मेहमानों के बैग चेक किए जा रहे थे और उन्होंने इन पाबंदियों की वैधता पर सवाल उठाया।

वैभव सूर्यवंशी ने नेट्स पर अभिषेक से क्यों कहा था 'भाग मिल्खा भाग' का डायलॉग? हुआ खुलासा



अभिषेक शर्मा ने खुलासा किया कि न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 से पहले वैभव सूर्यवंशी ने नेट्स पर 'भाग मिल्खा भाग' के डायलॉग से प्रेरित होकर कहा था, 'भैया, खेलूंगा भी वैसे ही।' वैभव ने 19 गेंदों में 45 रन बनाए, जबकि अभिषेक ने 38 गेंदों में 113 रन ठोके। भारत ने 199 रन का लक्ष्य 13.2 ओवर में हासिल कर छह विकेट से जीत दर्ज की। भारतीय टीम के युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बल्लेबाजी के पीछे की एक दिलचस्प कहानी साझा की है।

अभिषेक फिर पहुंचे शीर्ष पर, टेस्ट ऑलराउंडर में जडेजा की बादशाहत खत्म; गेंदबाज में कौन टॉप पर?



आईसीसी की ताजा रैंकिंग में अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजों में नंबर-1 का स्थान फिर हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के मार्को यानसेन टेस्ट गेंदबाज और ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गए, जिससे रवींद्र जडेजा की चार साल से अधिक समय से चली आ रही बादशाहत खत्म हुई। तेम्बा बावुमा, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह और अन्य खिलाड़ियों को भी फायदा हुआ। आईसीसी की ताजा पुरुष खिलाड़ी रैंकिंग में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में फिर से नंबर-एक बल्लेबाज का स्थान हासिल कर लिया है। वहीं, दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर मार्को यानसेन ने एक साथ टेस्ट गेंदबाज और टेस्ट ऑलराउंडर की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया। यानसेन ने टेस्ट ऑलराउंडरों की सूची में भारत के रवींद्र जडेजा को पीछे छोड़ दिया, जो चार साल से अधिक समय से इस स्थान पर काबिज थे। ताजा रैंकिंग में टेस्ट बल्लेबाजों और गेंदबाजों के साथ वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की सूची में भी कई बदलाव हुए हैं। अभिषेक शर्मा ने फिर हासिल किया नंबर-1 का ताज न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में तूफानी शतक लगाने का फायदा अभिषेक शर्मा को आईसीसी रैंकिंग में मिला है। भारतीय बाएं हाथ के बल्लेबाज ने ईशान किशन को पीछे छोड़कर टी20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष स्थान फिर से हासिल कर लिया। वेलिंगटन में खेले गए मुकाबले में अभिषेक ने केवल 35 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था। उन्होंने 38 गेंदों में 113 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसकी बदौलत भारत ने 199 रन का लक्ष्य 13.2 ओवर में चार विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत ने यह मुकाबला छह विकेट से जीता और पांच मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली। ईशान किशन ने इस साल जुलाई में आयरलैंड के खिलाफ अच्छे प्रदर्शन के बाद अभिषेक से नंबर-1 का स्थान हासिल किया था।

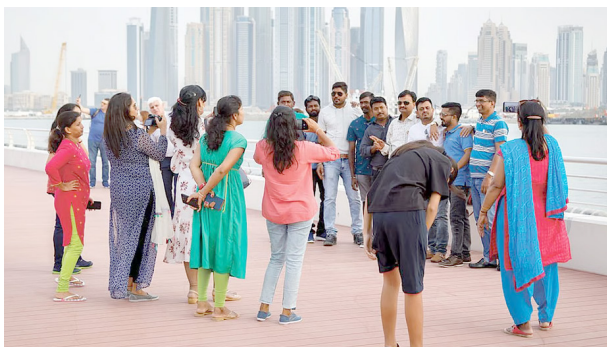
नेतन्याहू-गादी किसी को नहीं मिला चुनाव में बहुमत, अब आगे क्या होगा? कैसे बनेगी सरकार

इजरायल चुनाव के शुरुआती नतीजों ने राजनीतिक संकट बढ़ा दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू का गठबंधन बहुमत से दूर है, जबकि सरकार गठन में अरब समर्थित पार्टियों की भूमिका अहम हो सकती है। शुरुआती आंकड़ों में नेतन्याहू के गठबंधन को 57 सीटें मिलीं विपक्षी गुट को 47 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया सरकार गठन में अरब समर्थित पार्टियों की भूमिका अहम हो सकती है इजरायल के चुनाव नतीजों ने देश में राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ा दी है। शुरुआती एग्जिट पोल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन और पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइजेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्ष के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा का अनुमान लगाया गया था। इजरायल की 120 सदस्यीय नेसेट में बहुमत हासिल करने के लिए किसी भी गठबंधन को जरूरी 61 सीटें मिलने की संभावना नहीं जताई गई थी। इजरायल की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के शुरुआती आंकड़ों में नेतन्याहू के गठबंधन को 57 सीटें, जबकि उनके विरोधी गुट को 47 सीटें मिलती दिखाई दीं। स्थानीय समयानुसार सुबह 5:58 बजे तक 41.9% बैलेट बॉक्स की गिनती पूरी हुई थी। शेष 16 सीटें मुख्य रूप से अरब जॉइंट लिस्ट और रा'म गुटों के हिस्से में आईं। गिने गए वोटों में लिकुड को 28% और आइजेनकोट की याशर पार्टी को 21% वोट मिले। हालांकि, वोट प्रतिशत के आधार पर सीधे तौर पर सीटों की संख्या तय नहीं होती। सरकार गठन में अरब समर्थित पार्टियों की



भूमिका अहम एग्जिट पोल में अरब नेतृत्व वाली पार्टियों को लगभग 18 से 19 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में सरकार गठन को लेकर होने वाली बातचीत में इन दलों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि, नेतन्याहू और आइजेनकोट दोनों ने सरकार बनाने के लिए इन पार्टियों पर निर्भर रहने को लेकर अलग-अलग स्तर पर संदेह जताया है। चुनाव की रात अपने संबोधन में नेतन्याहू ने अरब नेतृत्व वाली पार्टियों के समर्थन पर निर्भर सरकार का विरोध दोहराया था। वहीं, आइजेनकोट ने कुछ शर्तों के साथ उनके सहयोग की संभावना के संकेत दिए। इस मुद्दे से विपक्षी गठबंधन के भीतर बातचीत जटिल हो सकती है। इजरायल में फिर होगें चुनाव? इजरायली राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि एग्जिट पोल ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या विपक्षी नेता अरब नेतृत्व वाले समूहों के साथ मिलकर काम करने को तैयार होंगे। अगर नेता अपने चुनावी वादों से पीछे नहीं हटते, तो आने वाले महीनों में एक बार फिर चुनाव होने की संभावना बन सकती है। 7 अक्टूबर के हमले और सैन्य सेवा का मुद्दा यह चुनाव 7 अक्टूबर 2023 को हमास के नेतृत्व में हुए हमलों और उसके बाद शुरू हुए युद्धों की पृष्ठभूमि में हुआ। नेतन्याहू के विरोधियों ने सुरक्षा व्यवस्था में हुई चूकों के लिए जवाबदेही की मांग की, जबकि उनके समर्थकों ने हमलों के बाद इजरायल की सैन्य कार्रवाइयों को अपनी दलील का आधार बनाया। इजरायल में पहले भी हो चुका है राजनीतिक गतिरोध इजरायल हाल के वर्षों में कई बार राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर चुका है। अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के बीच देश में तीन बार चुनाव कराने पड़े, क्योंकि राजनीतिक दल नेसेट में स्थिर बहुमत बनाने में विफल रहे थे। उस गतिरोध का अंत बेंजामिन नेतन्याहू और उनके तत्कालीन प्रतिद्वंद्वी बेनी गैंट्ज के बीच सत्ता-साझाकरण समझौते से हुआ था। इसके तहत दोनों नेताओं को बारी-बारी से प्रधानमंत्री बनना था। हालांकि, लगभग एक साल बाद बजट पारित नहीं हो पाने के कारण सरकार गिर गई और देश को एक बार फिर चुनाव का सामना करना पड़ा।

दुबई कमाने जाने से पहले सावधान! UAE में एक गलती से भरना पड़ सकता है लाखों का बिल



UAE जाने वाले भारतीयों के लिए भारत के दूतावास ने मेडिकल इंश्योरेंस को लेकर सलाह जारी की है। दुबई, अबू धाबी जाने से पहले जानें बीमा में किन खर्चों का कवर होना जरूरी है।

UAE जाने वाले भारतीयों को पर्याप्त मेडिकल इंश्योरेंस लेने की सलाह दी गई। बीमा में कैशलेस इलाज और मरीज को भारत वापस लाने का खर्च शामिल होना चाहिए। UAE में नौकरी करने वाले भारतीय भी अपने हेल्थ इंश्योरेंस की कवरेज जांच लें। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में नौकरी करने, परिवार के साथ रहने या घूमने जाने की तैयारी कर रहे भारतीय नागरिकों के लिए अहम सलाह जारी की गई है। भारत के राजनयिक मिशनों ने भारतीयों से अपील की है कि वे UAE जाने से पहले पर्याप्त मेडिकल इंश्योरेंस जरूर लें। बीमा में अचानक बीमार पड़ने या मेडिकल इमरजेंसी के दौरान इलाज के खर्च के साथ मरीज को वापस भारत लाने का खर्च भी शामिल होना चाहिए। भारतीय अधिकारियों के मुताबिक, UAE में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें गंभीर बीमारी या अचानक चिकित्सा जरूरत के कारण लोगों पर भारी अस्पताल बिल का बोझ पड़ गया। पर्याप्त बीमा नहीं होने के कारण मरीजों और उनके परिवारों के लिए इन खर्चों का भुगतान करना मुश्किल हो गया। भारतीय दूतावास ने क्या कहा? अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास और दुबई तथा उत्तरी अमीरात में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी की है। इसमें UAE की यात्रा करने वाले भारतीयों को यात्रा शुरू करने से पहले अपने मेडिकल इंश्योरेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। एडवाइजरी के अनुसार, बीमा में कैशलेस इलाज की सुविधा होने के साथ-साथ आपात स्थिति में मरीज को भारत वापस लाने यानी मेडिकल रिपैट्रिएशन का खर्च भी कवर होना चाहिए। इससे गंभीर बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में परिवार पर अचानक बड़ा आर्थिक बोझ पड़ने की आशंका कम हो सकती है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अमेरिकी रक्षा सचिव से मुलाकात, फिलीपींस में रक्षा संबधों पर चर्चा की



भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिलीपींस में अमेरिकी रक्षा सचिव से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के रक्षा संबंधों की समीक्षा की गई है। फिलीपींस में रक्षा मंत्री ने अमेरिकी रक्षा सचिव से मुलाकात की 13वें एडीएमएम-प्लस के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात रक्षा संबंधित संबंधों को लेकर समीक्षा की गई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को फिलीपींस के सेबू में 13वें दक्षिणपूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान रक्षा सचिव पीट हेगसेथ से मुलाकात की। रक्षा मंत्री ने अपने पोस्ट में कहा कि 13वें एडीएमएम-प्लस के दौरान अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ के साथ बैठक हुई। हमने सैन्य प्रौद्योगिकी, सूचना साझाकरण और सह-उत्पादन में रणनीतिक अभिसरण को बढ़ावा देने वाले अपने 10 वर्षीय भारत-अमेरिका रक्षा ढांचे की प्रगति की समीक्षा की। हमारी मजबूत साझेदारी एक स्वतंत्र, खुले और सुरक्षित इंडो-पैसिफिक के लिए आधारशिला बनी हुई है। फिलीपींस दौरे पर रक्षा मंत्री इससे पहले इसी बैठक के बारे में हेगसेथ ने एक पोस्ट में कहा था, "भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ शानदार बैठक हुई। हमने अपनी प्रमुख रक्षा साझेदारी के ढांचे की एक सालगिरह मनाई और सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया।" राजनाथ सिंह 28 से 29 अक्टूबर तक फिलीपींस के सेबू में आयोजित हो रही दक्षिणपूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) के 13वें रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। वे 'क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान' विषय पर मंच को संबोधित करेंगे।

रक्षा सहयोग को मजबूत करने का मंच एडीएमएम-प्लस के दौरान, रक्षा मंत्री सहभागी देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कर रहे हैं। वे इन देशों के साथ चल रहे रक्षा संबंधों की समीक्षा करेंगे और रणनीतिक साझेदारियों को और मजबूत करने के तरीकों पर विचार करेंगे।

गादी आइजनकोट कौन हैं? जिन्होंने इजरायल में नेतन्याहू को दी चुनौती; गाजा में बेटे को खोया



इजरायल के पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजनकोट प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी बनकर उभरे हैं। जानिए उनका सैन्य करियर और चुनावी एजेंडा क्या है। गादी आइजनकोट 2015 से 2019 तक इजरायल की सेना के प्रमुख रहे। गाजा युद्ध में बेटे की मौत के बाद आइजनकोट को व्यापक सहानुभूति मिली। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता उनके चुनावी एजेंडे के प्रमुख मुद्दे रहे। इजरायल की राजनीति में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को चुनौती देने वाले प्रमुख नेताओं में पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजनकोट का नाम चर्चा में है। आम चुनाव के शुरुआती एग्जिट पोल में विपक्षी गठबंधन को बढ़त मिलने के बाद आइजनकोट की भूमिका अहम हो गई है। हालांकि, किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण सरकार गठन को लेकर बातचीत निर्णायक होगी।

नेपाल के पूर्व सांसद ने छोड़ी चकाचौंध वाली जिंदगी, अब बकरियां बेचकर चलाते हैं घर; 15 परिवारों को भी दिखाई राह

नेपाल के पूर्व सांसद गमबहादुर श्रीष ने राजनीति के साथ खेती और पशुपालन को आजीविका बनाया। दो बकरियों से शुरू कारोबार में अब संतरे, शहद और मछली पालन भी शामिल हैं। नेपाल के पूर्व सांसद गमबहादुर श्रीष ने दो बकरियों और एक लाख नेपाली रुपये से कारोबार शुरू किया। अब 39 बकरियों के साथ संतरे की खेती, मधुमक्खी और मछली पालन से भी कमाई कर रहे हैं। उनकी पहल से गांव के 15 परिवारों ने व्यावसायिक बकरी पालन शुरू किया। ने 15 परिवारों ने अपनाया बकरी पालन श्रीष की कोशिशों से बरंजा गांव में कृषि उद्यमिता को बढ़ावा मिला है। उनके प्रयास से बने किसान समूह के रास्ते पर चलते हुए 15 परिवारों ने व्यावसायिक स्तर पर बकरी पालन शुरू किया है। उनका मानना है कि खेती और पशुपालन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और



आय बढ़ाने के प्रभावी माध्यम बन सकते हैं। राजनीति से अब भी जुड़े हैं श्रीष गमबहादुर श्रीष छात्र जीवन से ही सीपीएन (माओवादी) से जुड़े थे। वर्ष 2006 में वह अंतरिम विधायिका के सदस्य बने और 2008 से 2014 तक पहली संविधान सभा में प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद वह अपने गांव लौट आए और कृषि व्यवसाय पर ध्यान देने लगे। हालांकि, उन्होंने राजनीति से पूरी तरह दूरी नहीं बनाई है। वह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के केंद्रीय सदस्य हैं और खेती के साथ राजनीतिक गतिविधियों को भी जारी रखना चाहते हैं। पाल की राजनीति में करीब दो दशक तक सक्रिय रहे पूर्व सांसद गमबहादुर श्रीष इन दिनों खेती और पशुपालन के जरिए अपनी आजीविका चला रहे हैं। नेपाल के संविधान निर्माण की प्रक्रिया में शामिल रहे श्रीष ने गांव लौटकर स्वरोजगार का रास्ता चुना। अब वह बकरी पालन, संतरे की खेती, मधुमक्खी पालन और मछली पालन से कमाई कर रहे हैं। उनकी पहल से गांव के दूसरे परिवार भी कृषि व्यवसाय की ओर बढ़ रहे हैं। दो बकरियों से शुरू किया कारोबार नेपाली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, श्रीष ने करीब छह साल पहले दो बकरियों और एक लाख नेपाली रुपये के निवेश से अपना काम शुरू किया था। आज उनके फार्म में 39 बकरियां हैं। वह हर साल 15 से 20 बकरे बेचते हैं। उनके फार्म में खारी और जमुनापारी नस्ल की बकरियां पाली जाती हैं। शुरुआत में उन्हें नुकसान भी हुआ।

लंच ब्रेक के बाद छीन ली नौकरी! AI कंपनी Innodata ने बिना किसी नोटिस 550 भारतीय कर्मचारियों को निकाला

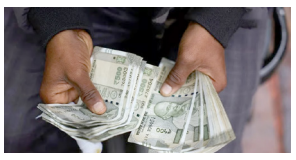
इनोडाटा ने भारत में 550 कर्मचारियों को अचानक नौकरी से निकाला, लंच ब्रेक के बाद लैपटॉप और ID का एक्सेस छीन लिया गया। जानें छंटनी के पीछे की वजह। इनोडाटा ने भारत में करीब 550 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। कर्मचारियों का लैपटॉप और अन्य डिवाइस का कंट्रोल उनसे छीन लिया गया। 26 अक्टूबर को इस कंपनी में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी हुई। डेटा इंजीनियरिंग और एआई सर्विस कंपनी इनोडाटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने भारत में करीब 550 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। कर्मचारियों की इस बात की जानकारी तब मिली, जब वे लंच के बाद वापस काम के लिए लौटे।



मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कर्मचारियों का लैपटॉप और अन्य डिवाइस का कंट्रोल उनसे छीन लिया गया। इसके अलावा उनकी ऑफिशियल ID भी डीएक्टिवेट हो गईं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि 26 अक्टूबर को इस कंपनी में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी हुई। फिलीपींस में इनोडाटा की छंटनी ऐसी जानकारी है कि भारत के साथ-साथ फिलीपींस के कर्मचारी भी इस छंटनी से प्रभावित हुए हैं। छंटनी होने वाले कर्मचारियों में रेटर्स, क्वालिटी एक्सपर्ट्स, टीम लीडर्स और मैनेजर्स जैसे जॉब रोल्स शामिल थे, जिन्हें Zoom मीटिंग के दौरान नौकरी से निकाल दिया गया। भारत में 550 कर्मचारियों को निकाला कुछ कर्मचारियों ने बताया कि कंपनी के एचआर पेरोल सिस्टम (HR Payroll System) पर उनके इस्तीफे की तारीख 26 अक्टूबर दर्ज मिली। खबर है कि मैनेजरों को भी नौकरी से निकाले जाने की कोई जानकारी नहीं थी। इसके बाद जिन चुने हुए कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया था, उन्हें उनके पर्सनल ईमेल ID पर टर्मिनेशन ईमेल मिले।

महंगाई भत्ता बढ़कर हुआ 63%, अब कितनी बढ़ जाएगी सैलरी; एरियर का भी समझें पूरा गणित

केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की। अब डीए 63% हो गया है। जानें सैलरी और एरियर में कितना होगा इजाफा। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह दिवाली से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक खास तोहफा है। अब कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 3% बढ़कर 63% हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने बुधवार



को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह दिवाली से पहले कर्मचारियों के लिए एक खास तोहफा है। सरकार के इस फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। इस फैसले से सरकार पर 10,016 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू होगी। सैलरी कितनी बढ़ सकती है? जुलाई से अक्टूबर तक के चार महीने का एरियर अक्टूबर की सैलरी के साथ कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक साथ दिया जाएगा। यदि आपकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो हर महीने 540 रुपये की बढ़ोतरी होगी। वहीं, 30,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर 900 रुपये मासिक बढ़ेंगे। 50,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर महंगाई भत्ते में 1,500 रुपये का इजाफा होगा। पेंशन में कितने की बढ़ोतरी? उदाहरण के लिए, यदि आपकी बेसिक पेंशन 18,000 रुपये है, तो हर महीने 540 रुपये की वृद्धि होगी। इसी प्रकार, 30,000 रुपये की बेसिक पेंशन पर 900 रुपये मासिक बढ़ेंगे। 50,000 रुपये की बेसिक पेंशन पर महंगाई राहत के तहत हर महीने 1500 रुपये की बढ़ोतरी होगी। 50 हजार पर छह हजार का एरियर यदि आपकी बेसिक सैलरी 18000 रुपये है, तो अक्टूबर की सैलरी के साथ 2160 रुपये एरियर मिलेगा।

जरांगे पाटील की 500 करोड़

नाराजगी जाहिर की। इस घटनाक्रम के बाद सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर आपसी तालमेल को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। निधि वितरण में कटौती पर भी सवाल बैठक में सरकारी निधि के वितरण का मुद्दा भी उठाया गया। सूत्रों के अनुसार, शिवसेना के मंत्रियों ने वित्त विभाग के कुछ अधिकारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल किया कि मंजूर निधि में कटौती करने का अधिकार अधिकारियों को किसने दिया। मंत्रियों ने संबंधित मामले में कार्रवाई की मांग भी की। भाजपा नेताओं के पलटवार के बाद बढ़ी चर्चा इससे पहले शिंदे गुट के नेता रामदास कदम ने ऑडियो क्लिप के मुद्दे पर भाजपा को निशाने पर लिया था। इसके जवाब में भाजपा नेताओं प्रवीण दरेकर और प्रसाद लाड ने पलटवार किया था। अब इस पूरे विवाद में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया और गठबंधन के नेताओं के अगले कदम पर नजरें टिकी हैं।

महाराष्ट्र में सरकारी भवनों का

साफ कर दिया है कि अगर किसी ने भी सरकारी भवनों का बजट बढ़ाया तो संबंधित अफसर सीधे नपेंगे। सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग के नए आदेश के अनुसार निर्माण योजनाओं में बिना मंजूरी फेरबदल पर पूरी रोक लगा दी गई है और अधिकारियों को अब तय लागत में ही पूरा प्रोजेक्ट पूरा करना होगा। यह भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि मूल नक्शे, मानकों या कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह के आवश्यक बदलाव के लिए अब सचिव स्तर की अनुमति जरूरी होगी, ताकि वित्तीय अनुशासन बना रहे और तय सीमा में काम पूरा हो सके। मंजूर नक्शों में किया जाता है बदलाव पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से जारी जीआर के अनुसार कई मामलों में मंजूर नक्शों में बदलाव कर सुरक्षा दीवार, सड़क और फर्नीचर जैसे कार्यों को अनुमान से बाहर रखा जा रहा है। वहीं, अतिरिक्त क्षेत्रफल, फॉल्स सीलिंग, आंतरिक सड़कें, एसी सिस्टम और ट्रांसफॉर्मर जैसे काम उपयोगकर्ता विभाग की लिखित मंजूरी के बिना शामिल किए जा रहे हैं। इससे परियोजना की लागत बढ़ती है और भवन का समय पर उपयोग शुरू नहीं हो पाता। अधूरे काम की निविदा प्रक्रिया तक शुरू नहीं होगी शासन परिपत्र के अनुसार यदि तकनीकी अनुमान मंजूर लागत से अधिक है, तो महाराष्ट्र सरकार को तत्काल सूचित कर नई प्रशासनिक मंजूरी के लिए संशोधित प्रस्ताव भेजना होगा। नई मंजूरी मिलने तक अधूरे काम की निविदा प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। निर्माण के मानकों, मात्रा या कार्यक्षेत्र में बदलाव के लिए संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सचिव की लिखित अनुमति जरूरी होगी। संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी होगी तय मुख्य अभियंता और अधीक्षक अभियंता को यह सुनिश्चित करना होगा कि बदलावों से मंजूर लागत न बढ़े। तकनीकी मंजूरी देने वाले अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि पूरा काम निर्धारित बजट में संपन्न हो और भवन उपयोग के लिए सौंपा जाए। उच्चाधिकार समिति की नाराजगी के बाद जारी इन निर्देशों का सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को कड़ाई से पालन करना होगा। उल्लंघन कर संशोधित मंजूरी के प्रस्ताव भेजने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

सुनेत्रा पवार ने जीशान सिद्दीकी

उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार और सांसद पार्थ पवार का आभार जताया है। जीशान सिद्दीकी ने सुनेत्रा पवार और पार्थ का जताया आभार मुंबई NCP अध्यक्ष के रूप में अपनी नियुक्ति पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के MLC जीशान सिद्दीकी ने कहा कि यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो सुनेत्रा वहिनी और पार्थ दादा ने आज मुझे अपने नेतृत्व में सौंपी है। उन्होंने मुझे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) का मुंबई अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह मेरे और मेरी पूरी टीम के लिए बहुत बड़ी बात है। अब मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद करना हमारी जिम्मेदारी है। सु जीशान ने वित्त मंत्रालय पर ठोका दावा NCP के मुंबई अध्यक्ष बनते ही जीशान सिद्दीकी ने वित्त मंत्रालय पर दावा ठोक दिया है। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग हमेशा अजित पवार के पास रहा है, और आज भी हम सभी का मानना है कि वहिनी साहिब (सुनेत्रा पवार) इसे संभालने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। नेत्रा वहिनी मां समानः जीशान सिद्दीकी मुंबई NCP अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के बाद जीशान सिद्दीकी ने सुनेत्रा पवार को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि वहिनी (भाभी) हमेशा मेरे लिए एक मां की तरह रही हैं, और पार्थ दादा हमेशा एक बड़े भाई की तरह रहे हैं। वहिनी साहिब हमेशा एक मां की तरह रही हैं, और मैं उनके भरोसे पर खरा उतरूंगा। जीशान सिद्दीकी ने कहा कि इससे पहले भी उन्होंने मुझे MLC का पद दिया था, और अब उन्होंने मुझे मुंबई अध्यक्ष बनाया है। मैं उनका आभारी हूं। मैं पूरी कोशिश सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाऊं। जीशान सिद्दीकी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि महायुति गठबंधन के भीतर, हमें वित्त विभाग वापस जरूर मिलेगा। पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को यही उम्मीद है, और मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसा जल्द ही होगा।

मुंबई में 30 अक्टूबर से

रखने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर पुतले या प्रतीकात्मक शव प्रदर्शित करने, भड़काऊ भाषण देने और आपत्तिजनक नारे लगाने जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश में तेज आवाज में लाउडस्पीकर पर संगीत बजाने पर भी रोक का उल्लेख है। बैनर और होर्डिंग पर भी रहेगी नजर मुंबई पुलिस के आदेश के अनुसार, सार्वजनिक शालीनता और नैतिकता के लिए खतरा पैदा करने वाले बैनर या होर्डिंग लगाने पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। प्रतिबंधों का उद्देश्य शहर में शांति बनाए रखना और किसी भी संभावित अप्रिय घटना को रोकना है। यह आदेश 28 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे प्रतिबंधों की शर्तों का पालन करें और किसी भी ऐसी गतिविधि से बचें, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

पृष्ठ 1/8 का शेष

गोरेगांव में निर्माण कार्यों

का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह के समय जब लोग काम पर निकलते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और वरिष्ठ नागरिक टहलने के लिए बाहर आते हैं, तब धूल के कारण उन्हें परेशानी होती है। नियमित पानी के छिड़काव की व्यवस्था नहीं स्थानीय नागरिकों की प्रमुख शिकायत यह है कि निर्माण कार्यों के दौरान उड़ने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए नियमित पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि यदि निर्माण स्थलों, आसपास की सड़कों और धूल प्रभावित हिस्सों में नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाए तो धूल के उड़ने में कमी लाई जा सकती है। इसके अलावा निर्माण सामग्री को ढक कर रखने, मलबे का सुरक्षित परिवहन करने और निर्माण स्थलों पर निर्धारित प्रदूषण नियंत्रण उपायों का पालन कराने की भी जरूरत है। गो बीएमसी से कार्रवाई की मांग नागरिकों ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका से गोरेगांव में बढ़ती धूल और प्रदूषण की समस्या पर ध्यान देने की मांग की है। उनका कहना है कि संबंधित विभाग को निर्माण स्थलों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। जिन स्थानों पर धूल नियंत्रण के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं, वहां आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। स्थानीय लोगों की मांग है कि प्रभावित सड़कों पर नियमित सफाई और पानी के छिड़काव की व्यवस्था की जाए और निर्माण स्थलों पर धूल को हवा में फैलने से रोकने के लिए प्रभावी उपाय लागू किए जाएं। रेगांव में विकास कार्यों के साथ नागरिकों के स्वास्थ्य और स्वच्छ वातावरण का ध्यान रखना भी जरूरी है। यदि समय रहते निर्माण स्थलों पर प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तो धूल से होने वाली परेशानी को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अब देखना यह है कि बीएमसी इस समस्या को दूर करने के लिए क्या कदम उठाती है।

MMR में 2051 तक नहीं होगी

व्यवस्था को मजबूत बनाने के उपायों पर विस्तृत अध्ययन करेगी। भविष्य की जल सुरक्षा साथ ही 3 माह के भीतर सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपेगी, जिससे पूरे महानगर क्षेत्र को निर्बाध पानी मिल सके। महाराष्ट्र सरकार के जल संसाधन विभाग ने इस संबंध में जीआर जारी किया है। अध्ययन समूह की अध्यक्षता जल संसाधन विभाग के सेवानिवृत्त सचिव डॉ. संजय बेलसरे करेंगे। समूह में मुंबई बीएमसी, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ठाणे, नवी मुंबई और कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल, महाराष्ट्र रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर और महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। कोंकण क्षेत्र के जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता सदस्य सचिव होंगे। अध्ययन समूह के अध्यक्ष जरूरत पड़ने पर दूसरे विभागों, संस्थाओं, स्थानीय निकायों और विशेषज्ञों को भी बैठकों में आमंत्रित कर सकेंगे। भविष्य की मांग का आकलन मुंबई महानगर क्षेत्र में घरेलू, औद्योगिक और व्यावसायिक जरूरतों को देखते हुए वर्ष 2031, 2041 और 2051 के लिए पानी की मांग और संभावित कमी का अनुमान लगाया जाएगा। अध्ययन समूह इन अनुमानों की तुलना उपलब्ध और भविष्य में मिलने वाले पानी से करेगा। इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि किस क्षेत्र में कितने पानी की जरूरत होगी और आने वाले वर्षों में कहां कितनी कमी हो सकती है। परियोजनाओं की समीक्षा मौजूदा बांधों, जलाशयों, नदियों और भूजल की तकनीकी जांच होगी। साथ ही पूरी हो चुकी, निर्माणाधीन और प्रस्तावित जल परियोजनाओं से मिलने वाले अतिरिक्त पानी का हिसाब तैयार होगा। वैकल्पिक स्रोत और बर्बादी पर लगी रोक शोधित सीवेज के पानी का दोबारा इस्तेमाल, रेनवाटर हार्वेस्टिंग और भूजल पुनर्भरण घर जोर रहेगा, पाइपलाइन रिसाव रोककर गैर-राजस्व जल की बर्बादी न्यूनतम की जाएगी। जलवायु परिवर्तन से तालमेल अनियमित बारिश, सूखा, अतिवृष्टि और समुद्र स्तर में वृद्धि के असर को देखते हुए एक टिकाऊ और लचीली कार्ययोजना बनेगी। लागत और समयबद्ध रोडमैप 2051 तक की जरूरतों के अनुसार नई परियोजनाओं की प्राथमिकताएं, अनुमानित बजट, समयसीमा और विभागों की जवाबदेही तय की जाएगी।

महाराष्ट्र में Ola, Uber और

रखने के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। परिवहन विभाग और पुलिस बल आपसी तालमेल से काम करते हुए सभी शिकायतों का त्वरित समाधान करेंगे। उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई परिवहन मंत्री सरनाईक ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन कंपनियों के साथ काम करने वाले चालकों की पृष्ठभूमि, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन संबंधी वैध कागजात और तय शर्तों की बारीकी से जांच हो। जांच के दौरान यदि कोई भी नियम उल्लंघन, धोखाधड़ी या गैरकानूनी गतिविधि पाई जाती है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ कोई अप्रिय घटना घटने के बाद ही कार्रवाई करने के बजाय एक स्थायी निगरानी तंत्र विकसित होना चाहिए। इसके तहत इन सेवाओं को राज्य परिवहन प्राधिकरण के दायरे में प्रभावी रूप से लाने की जरूरत है। अगर मौजूदा कानूनी प्रावधान इन चालकों को पूरी तरह नियमबद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, तो सरकार एक नया और संशोधित कानून लाने के विकल्प पर भी गंभीरता से काम करेगी।

संजय राउत की बढ़ेंगी मुश्किलें!

था कि राउत द्वारा बताई गई वह तस्वीर लंदन की बिल्कुल नहीं थी, बल्कि दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम की थी। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी संजय राउत के खिलाफ यह याचिका बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय द्वारा सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक अवमानना के तहत दायर की गई थी। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमालिया बागची की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए बेहद कड़ी टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि देश के न्यायपालिका जैसे संवैधानिक संस्थानों पर ऐसे निराधार हमले अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। साथ ही, अदालत ने यह भी सवाल पूछा था कि क्यों न इनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। शुरुआती दौर में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से राहत दी थी, लेकिन रिकॉर्ड पूरा न होने के कारण अब राउत को 17 नवंबर को अनिवार्य रूप से अदालत में हाजिर होने का नया नोटिस जारी किया गया है।

दैनिक सिटी न्यूज मुंबई
CITY NEWS MUMBAI
गुरुवार , 29 अक्टूबर 2026, ठाणे, मुंबई

भिवंडी में मनपा का बुलडोजर एक्शन! अनधिकृत पतरे की 5 दुकानों पर कार्रवाई

नारपोली-2 में घर नंबर 223, सर्वे नंबर 107 पर चला बुलडोजर; नोटिस के बाद भी दुकानें नहीं हटाने पर मनपा ने की कार्रवाई

सिटी न्यूज़ मुंबई/गनी खान

भिवंडीः शहर में अनधिकृत निर्माण के खिलाफ भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका ने सख्त रुख अपनाते हुए नारपोली-2 इलाके में पांच दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की। घर नंबर 223, सर्वे नंबर 107 स्थित इन दुकानों को कथित तौर पर अनधिकृत पतरे के सेट से बनाया गया था। मनपा की इस कार्रवाई से इलाके में हलचल मच गई।

मनपा प्रभाग समिति क्रमांक-4 के सहायक आयुक्त ने बताया कि संबंधित जगह पर पतरे के अनधिकृत सेट तैयार कर पांच दुकानें बनाई गई थीं। इन दुकानों को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं। प्रशासन की ओर से पहले नोटिस देकर अनधिकृत निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद दुकानें नहीं हटाए जाने पर मनपा ने कार्रवाई करते हुए



बुलडोजर चलाया।

कार्रवाई के दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन की टीम तैनात रही। पुलिस स्टेशन के प्रभारी विक्रम मोहिते के मार्गदर्शन में पुलिस बंदोबस्त लगाया गया था। मनपा की इस कार्रवाई को अनधिकृत निर्माण के खिलाफ प्रशासनिक कदम के रूप में देखा जा रहा है।

इस कार्रवाई के बाद सवाल उठता है कि शहर में अनधिकृत निर्माण के खिलाफ निगरानी और कार्रवाई कितनी प्रभावी है। नोटिस के बावजूद निर्माण नहीं हटाए जाने पर बुलडोजर चलाना यह संकेत देता है कि मनपा अब शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ रही है। हालांकि, शहर में अन्य कथित अनधिकृत निर्माणों पर भी इसी तरह कार्रवाई होगी या नहीं, इस पर नागरिकों की नजर रहेगी।

MMR में 2051 तक नहीं होगी अब पानी की किल्लत मुंबई रीजन के लिए बना 25 साल का वॉटर प्लान

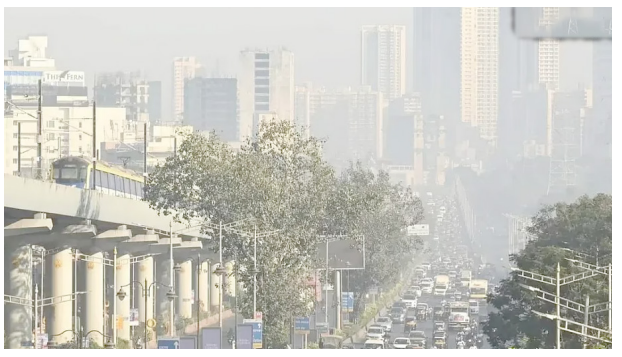


मुंबई रीजन में 2051 तक पानी की किल्लत खत्म करने राज्य सरकार ने 25 साल का वॉटर प्लान तैयार करने हेतु पूर्व सचिव डॉ. संजय बेलसरे की अध्यक्षता में कमेटी गठित की। मुंबई रीजन के लिए 2051 तक का वॉटर प्लान तैयार होगा। डॉ. संजय बेलसरे की अध्यक्षता में विशेषज्ञ कमेटी गठित। सीवेज रीसाइक्लिंग, लीकेज रोकने और जल परियोजनाओं पर 3 महीने में रिपोर्ट। मुंबई रीजन में भविष्य की जल सुरक्षा सुनिश्चित करने और वर्ष 2051 तक संभावित पानी की किल्लत को जड़ से खत्म करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 25 साल का व्यापक वॉटर प्लान तैयार करने का बड़ा कदम उठाया है। इस दीर्घकालीन योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए जल संसाधन विभाग के पूर्व सचिव डॉ. संजय बेलसरे की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी सीवेज रीसायकलिंग, पाइपलाइन लीकेज रोकने और आपूर्ति ...शेष 7 पर

गोरेगांव में निर्माण कार्यों से फैली धूल और प्रदूषण पर भड़के लोग

BMC से सख्त कार्रवाई की उठी जोरदार मांग

गोरेगांव में निर्माण स्थलों से उड़ती धूल और बढ़ते प्रदूषण से नागरिक परेशान हैं। स्थानीय नेताओं ने बीएमसी से नियमों का पालन न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। गोरेगांव में निर्माण कार्यों के चलते धूल और प्रदूषण बढ़ा। नियमित पानी के छिड़काव और निर्माण सामग्री ढकने की व्यवस्था पर सवाल। नागरिकों ने बीएमसी से निरीक्षण और सख्त कार्रवाई की मांग की। गो चल रहे निर्माण कार्यों, सड़कों पर फैली मिट्टी और निर्माण सामग्री ले जाने वाले ट्रकों के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे स्थानीय नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह करीब 7:45 बजे गोरेगांव के कई हिस्सों में धुंध जैसी स्थिति दिखाई दे रही थी। हवा में धूल के कणों की मौजूदगी के



कारण प्रदूषण का असर साफ महसूस किया जा सकता है। गोरेगांव में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य चल रहे हैं और इनके दौरान प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी जांच की जानी चाहिए। मनपा आयुक्त, राज्य सरकार और संबंधित प्रदूषण नियंत्रण विभाग को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। रेगांव में सुबह होते ही हवा में धूल और मिट्टी के कण फैलने से प्रदूषण की समस्या गंभीर होती दिखाई दे रही है। इलाके में बड़े पैमाने पर चल रहे निर्माण कार्यों के कारण उड़ती धूल स्थानीय नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। सुबह के समय कई जगहों पर वातावरण धूल से भरा नजर आने की शिकायतें सामने आ रही हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण स्थलों पर धूल को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए जा रहे हैं। विशेष रूप से पानी के नियमित छिड़काव की व्यवस्था नहीं होने से समस्या और बढ़ रही है। गोरेगांव और आसपास के इलाकों में विकास कार्यों और निर्माण गतिविधियों के चलते बड़ी मात्रा में मिट्टी, रेत और निर्माण सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल हवा के साथ आसपास की सड़कों, रिहायशी इमारतों और दुकानों तक पहुंचती है। वाहनों की आवाजाही से भी सड़क पर जमी धूल दोबारा हवा में फैल जाती है। इससे स्थानीय नागरिकों को रोजाना धूल भरे वातावरण ...शेष 7 पर

मुंबई में 30 अक्टूबर से 28 नवंबर तक धारा 37 लागू: हथियार

लाउडस्पीकर और भड़काऊ भाषणों पर सख्त प्रतिबंध

मुंबई पुलिस ने शहर में शांति बनाए रखने 30 अक्टूबर से 28 नवंबर तक धारा 37 लागू की है। हथियार ले जाने, भड़काऊ भाषण देने और लाउडस्पीकर बजाने पर सख्त रोक रहेगी। मुंबई में 30 अक्टूबर से 28 नवंबर तक पुलिस प्रतिबंधात्मक आदेश लागू। हथियार, विस्फोटक और पत्थर ले जाने पर रोक। भड़काऊ भाषण, आपत्तिजनक नारे और तेज संगीत पर प्रतिबंध। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। पुलिस उपायुक्त (संचालन) अकबर पठान ने महाराष्ट्र



पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 37 के तहत यह आदेश जारी किया है। इसके अनुसार, प्रतिबंध 30 अक्टूबर 2026 को रात 12:01 बजे से शुरू होकर 28 नवंबर 2026 की रात 12 बजे तक लागू रहेंगे। इस अवधि में शहर में संभावित आंदोलनों, उपद्रव और सार्वजनिक शांति भंग करने वाली गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। पुलिस ने नागरिकों से नियमों का पालन करने की अपील की है। हथियार और खतरनाक वस्तुएं ले जाने पर रोक आदेश के तहत मुंबई शहर में हथियार, आग्नेयास्त्र, तलवार, भाला, चाकू, लाठी और शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली अन्य वस्तुएं ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा विस्फोटक सामग्री, संक्षारक पदार्थ, पत्थर और पत्थर फेंकने के लिए इस्तेमाल किए जा सकने वाले उपकरणों को बनाने, जमा करने या अपने साथ ले जाने पर भी रोक रहेगी। भड़काऊ भाषण और आपत्तिजनक नारों पर प्रतिबंध सार्वजनिक शांति बनाए ...शेष 7 पर

भिवंडी की समस्याओं को लेकर उद्धव ठाकरे गुट ने मनपा आयुक्त से की मुलाकात



पानी चोरी रोकने, गड्ढामुक्त सड़कों, प्रदूषण नियंत्रण और कामवारी नदी की सफाई की उठाई मांग

सिटी न्यूज़ मुंबई/गनी खान

भिवंडीः शहर की बुनियादी समस्याओं को लेकर शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार, 28 अक्टूबर को मनपा आयुक्त अनमोल सागर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने कम बारिश के चलते संभावित जलसंकट को देखते हुए पानी चोरी पर रोक लगाने और साइजिंग, डाइंग व सर्विस सेंटर जैसे उद्योगों की जलखपत नियंत्रित कर नागरिकों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने की मांग की। इसके अलावा शहर की सड़कों को गड्ढामुक्त करने, उड़ानपुलों की मरम्मत, प्रदूषण नियंत्रण, फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने और यातायात जाम की समस्या दूर करने पर जोर दिया गया। प्रतिनिधिमंडल ने कामवारी नदी की सफाई और सुभाष उद्यान के सुंदरीकरण की मांग भी उठाई। इस दौरान जिला सहसंपर्क प्रमुख मनोज गगे, शहर प्रमुख गजेंद्र गुलवी, पूर्व शहर प्रमुख मोहन वल्लाल, वैशाली मेस्त्री, नजीर शब्बीर शेख, हर्षल राऊत, राजू पातकर सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

यह दैनिक मालक-मुद्रक-प्रकाशक, संपादक मोहम्मद शकील अब्दुल रफीक ने सिटी इन्टरप्राजेस धरती कॉम्पलेक्स शॉप नं. 11, एवरशाईन नगर, मिरा रोड (पूर्व), जिल्हा - ठाणे से प्रकाशित किया, मुख्य कार्या लय- धरती कॉम्पलेक्स शॉप नं. 11, एवरशाईन नगर, मिरा रोड (पूर्व), जिल्हा - ठाणे महाराष्ट्र।मुंबई कार्या लय- शॉप नं. 14 उपाध्याय इंडस्ट्रियल इस्टेट, दहिसर चेक नाका, मुंबई इस समाचार पत्र में प्रकाशित सभी समाचारों से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है किसी भी विवाद का निपटारा मा. ठाणे न्यायालय के अधीन होगा संपादक मो. शकील अ. रफीक : मो. 9869128483
Email : shakeelsahara@gmail.com / citynewsmumbai@gmail.com website : www.citynewsmumbai.in RNI No. : MAHHIN/2012/47486